सुविचार
जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, वह अधूरा है एवं जिस नारी में पुरुषत्व नहीं, वह भी अपूर्ण है।
-रामधारी सिंह 'दिनकर'

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi • Saturday, 08 November 2025 • Year : 03 • Issue : 290 • Ranchi Edition • Page : 12 • Price : ₹3 • www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

Nikki Tamboli's Boyfriend Arbaaz Patel 'Nearly... 12

SHARE

सेंसेक्स	:	83,216.28
निफ्टी	:	25,492.30

SARAFA

सोना	:	11,335.00
चांदी	:	165.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

झारखंड-बिहार के सीमावर्ती इलाके से माओवादी निशांत अरेस्ट

PATNA : पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद और दूसरे चरण के मतदान से पहले झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके से एक कुख्यात माओवादी निशांत सोरेन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की पुष्टि झाझा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार ने की है। गिरफ्तार निशांत सोरेन को चिहरा थाना क्षेत्र के राजाडूमर से गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान में सीआरपीएफ और एसटीएफ की टीम भी शामिल थी। पूछताछ के दौरान निशांत सोरेन ने संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया, जिससे पुलिस को आगामी चुनाव में इलाके में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सीबीआई ने सीसीएल के मैनेजर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

NEW DELHI : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड के सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के डाकरा प्रोजेक्ट ऑफिस के मैनेजर और पर्सनल-एचआर दीपक गिरी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार की। सीबीआई के मुताबिक एजेंसी ने गुरुवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपी ने 50 हजार रुपये की पहली किस्त स्वीकार करने पर सहमति जताई।

हिसार में पुलिसकर्मी की पीट-पीटकर हत्या पांच हुए गिरफ्तार

HISAR : हरियाणा पुलिस के एक उपनिरीक्षक (57 वर्ष) की अपने घर के बाहर लोगों के एक समूह को हंगामा करने से रोकने की कोशिश करने के बाद कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि श्याम लाल इलाके में उपनिरीक्षक रमेश कुमार की ईंटों और लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कहा कि कुमार की डांट के बाद समूह वहां से चला गया, लेकिन फिर वापस आकर उन पर ईंटों से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई।

वंदे मातरम् सिर्फ शब्द नहीं, भारत की आत्मा और संकल्प का स्वर : पीएम

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित

- कार्यक्रम में मोदी ने विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी किया जारी
- कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा- 1937 में हटाए गए वंदे मातरम् के महत्वपूर्ण छंद
- आज भी देश के लिए बड़ी चुनौती है विभाजनकारी मानसिकता
- 'ऑपरेशन सिंदूर' में दुनिया ने देखा कि भारत जानता है दुर्गा का रूप धारण करना

NEW DELHI @ PTI : शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक सपना और एक संकल्प है। यह गीत मां भारती के प्रति भक्ति और समर्पण की प्रतीक भावना है, जो हमें अपने अतीत से जोड़ता है, वर्तमान में आत्मविश्वास भरता है और भविष्य के लिए साहस देता है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्षभर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने वंदे मातरम् पर विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। उन्होंने कांग्रेस पर स्पष्ट रूप से हमला करते हुए कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया था, जिसने विभाजन के बीज बोए और इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता देश के लिए आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। मोदी ने इस अवसर पर यहां इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में आगे उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् का मूल भाव है भारत मां भारती भारत की शाश्वत संकल्पना। जब यह चेतना शब्दों और लय के रूप में प्रकट हुई, तब वंदे मातरम् जैसी रचना सामने आई। गुलामी के दौर में यही उद्घोष भारत की स्वतंत्रता का संकल्प बन गया था। वंदे मातरम् स्वतंत्रता संग्राम का स्वर बन गया, जो हर क्रांतिकारी की जुबान पर और हर भारतीय की भावना में रचा-बसा था। प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम् को हर युग में प्रासंगिक बताया और 'ऑपरेशन सिंदूर' का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा, जब दुश्मन ने आतंकवाद का इस्तेमाल करके हमारी सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो दुनिया ने देखा कि भारत दुर्गा का रूप धारण करना जानता है।

बंग भंग आंदोलन में बना विरोध का प्रमुख नारा

प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम् के 150 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को भी याद करते हुए कहा कि बंकिमचंद्र चटर्जी ने जब 1875 में इसे बंगदर्शन में प्रकाशित किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन जाएगा। 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया जबकि 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान यह विरोध का प्रमुख नारा बना। वंदे मातरम् ने न केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता को एक किया, बल्कि एक समृद्ध सुजलाम सुफलाम भारत का सपना भी जगाया।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा था यह गीत

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा था और आज भी यह आजादी की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। बंकिम बाबू ने मां भारती को ज्ञान की देवी सरस्वती समृद्धि की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया। यही भाव आज भारत को विज्ञान तकनीक रक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अग्रणी बना रहा है। जब भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, जब हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ाने लगीं या विज्ञान से लेकर खेल तक नई ऊंचाइयां छूने लगीं तो हर भारतीय के दिल से एक ही स्वर निकला भारत माता की जय, वंदे मातरम्। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम् केवल स्वतंत्रता का गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने इस अवसर पर सभी ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया जिन्होंने वंदे मातरम् का उद्घोष करते हुए अपना जीवन न्योछावर किया।

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव : सीएम हेमंत ने बाबूलाल को बताया बैल, कहा-

झामुमो में खा-पीकर हुए मोटे आज भाजपा का जोत रहे हल

- बीजेपी ने 18 साल तक राज कर झारखंड को बना दिया खोखला
- राज्य में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही सरकार

PHOTON NEWS GHATSHILA : घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन आए। धालभूमगढ़ के नरसिंहगढ़ हाट मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जो भी उद्योग-धंधे लगाएंगे या चला रहे हैं, उस कंपनी को 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। जो कंपनी स्थानीय को रोजगार नहीं देगी, उसे कंपनी स्थापित नही करने दिया जाएगा। सरकार राज्य में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है, 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला धनबल, जनबल और अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा से ही झामुमो का है। वे लोग आप लोगों को विभिन्न प्रकार का लोभ-लालच देंगे, लेकिन उसमें फसना नहीं है। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि झामुमो में खा-पीकर मोटे हो गए और जब काम करने का समय आया तो हल भाजपा का जोत रहे हैं। ऐसे धोखेबाज प्रत्याशी से आपलोगों को बचकर रहना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने घाटशिला विधानसभा के विकास को लेकर कई सपने देखे थे। उनके कारण ही मुसाबनी में इंजीनियरिंग कॉलेज और जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने की स्वीकृति दी गई थी। दुर्भाग्यवश आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अधूरे सपने को आपका आशीर्वाद मिला तो सोमेश सोरेन पूरी मेहनत से पूरा करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा गरीब, मजदूर एवं किसान विरोधी पार्टी है। झारखंड बने 25 साल हो गए, 18 साल तक इसी पार्टी ने झारखंड में राज किया और राज्य को लूटकर खोखला बना दिया।

उद्योग चलाने वालों को देना होगा 75% रोजगार

हर मोर्चे पर हेमंत सरकार विफल : अर्जुन मुंडा

GHATSHILA : शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा घाटशिला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में समर्थन जताते हुए दावा किया कि जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है। मुंडा ने कहा कि झारखंड को राज्य बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने एक शिशु के रूप में राज्य की तुलना करते हुए कहा कि राज्य की उम्र भले ही 25 वर्ष हो गई हो, लेकिन विकास की गति अभी भी बेहद धीमी है। सरकार की विफल नीतियों और गलत प्राथमिकताओं के कारण झारखंड पीछे रह गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास जैसे तमाम क्षेत्रों में ठोस पहल देखने को नहीं मिली। मुंडा ने आरोप लगाया कि एक ओर लोगों में बेरोजगारी और असुरक्षा की भावना बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने प्रभावी पेसा कानून लागू करने में भी गंभीरता नहीं दिखाई।

बिहार को विकास के रास्ते पर लाने का मोदी-नीतीश सरकार ने किया काम : अमित शाह

विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण

- केंद्रीय गृह मंत्री ने राजग प्रत्याशी के समर्थन में जमुई में की चुनावी जनसभा
- लालू-राबड़ी के शासन में अपहरण, फिरौती और नरसंहार की घटनाओं का किया जिक्र

AGENCY JAMUI : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद सियासी दिग्गजों ने दूसरे चरण में अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जमुई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवार के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से समर्थन मांगा। अमित शाह ने कहा कि कभी लाल गलियारे का गढ़ माने जाने वाला जमुई आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने बिहार से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर विकास के मार्ग पर बिहार को लाने का काम किया है। अमित शाह ने उन्होंने लालूझराबड़ी शासन पर हमला करते हुए कहा कि उन दिनों बारात जाती थी, तो उगाही के लिए लोग कट्टा लेकर पहुंच जाते थे। अपहरण, फिरौती और नरसंहार आम बात थी। यही था उस दौर का बिहार। उसी जंगलराज ने राज्य की फैक्ट्रियां और कारोबार बंद करा दिए और बिहार को गरीबी की ओर धकेल दिया।

महागठबंधन की सरकार बनी तो रोजगार पर दिया जाएगा विशेष जोर : राहुल गांधी

- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भागलपुर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित
- शिक्षा में अव्वल बनाने के लिए लौटाया जाएगा नालांदा विश्वविद्यालय का प्राचीन गौरव

AGENCY BHAGALPUR : शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से महागठबंधन उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष बल दिया जाएगा। यह सरकार गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, किसान, मजदूर और युवाओं की होगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के नालांदा विश्वविद्यालय का प्राचीन गौरव लौटाया जाएगा। इसे विकसित किया जाएगा। यहां पूर्व की तरह विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के बुनकरों और मखाना किसान के लिए बाजार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि उनको उनके उत्पाद का उचित कीमत मिल सके। राहुल गांधी ने यहां एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) वोट चोरी का प्लान पूरे देश में लागू करना चाहती है। इन्होंने हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में यही काम किया है। अब ये यही काम बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक दिन में लेट हुए 300 से अधिक विमान

- ऑटोमैटिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी

NEW DELHI @ PTI : शुक्रवार को एयरपोर्ट पर उड़ान भरने में 300 से अधिक विमानों को देर हुई। एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी को फ्लाइट्स का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था। ऑटोमैटिक मैसेज स्विच सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। यह प्लेन के शेड्यूल यानी टेकऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। एटीसी अधिकारी पहले से मौजूद डेटा के मुताबिक मैन्युअली फ्लाइट शेड्यूल तैयार कर रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने का असर बाकी एयरपोर्ट्स पर भी दिखा। दिल्ली से वहां आने-जाने वाली फ्लाइट भी लेट हुईं। उड़ानों के रूट को ट्रैक करने वाले पोर्टल 'फ्लाइट अवेयर' ने दिल्ली के आसमान में मंडरा रहे विमानों के लोकेशन को ग्राफिक के जरिए दिखाया। इसमें कई फ्लाइट्स को एक ही जगह चक्कर लगाते देखा जा सकता है। गुरुवार की शाम से ही एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी थी।

झारखंड की पहली महिला प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा ने किया पदभार ग्रहण

- फिलहाल झारखंड का स्थापना दिवस पहली प्राथमिकता
- बेसिक पुलिसिंग पर रहेगा विशेष जोर, एक टीम की तरह काम करेगी पुलिस
- संगठित अपराध और नक्सलियों के खिलाफ जारी रहेगी करवाई

सीएम से की मुलाकात

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य की नवनियुक्त प्रभारी पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने मुलाकात की। प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को झारखंड की पहली महिला प्रभारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईपीएस) की अधिकारी तदाशा मिश्रा ने पदभार ग्रहण कर लिया। पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता झारखंड का स्थापना दिवस है। इसके अलावा बेसिक पुलिसिंग पर उनका विशेष जोर रहेगा। संगठित अपराध और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस एक टीम की तरह काम करेगी, किसी व्यक्ति विशेष पर सब कुछ निर्भर नहीं करेगा। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एक टीम सब कुछ कर सकती है।

हेल्थ अलर्ट आज के बच्चे अनुशंसित सीमा से कई गुना अधिक खाते हैं शुगर

बचपन में ज्यादा चीनी की आदत स्मरण शक्ति के लिए बड़ी बाधा

PHOTON NEWS, RESEARCH DESK : यह सामान्य रूप से कहा जाता है कि बचपन की कई आदतें भविष्य के जीवन के लिए अत्यंत सुखद होती हैं। कई बुरी आदतें बाद में जीवन के लिए कष्टदायक भी बन जाती हैं। हाल में हुए रिसर्च में यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए एक निश्चित मात्रा में चीनी की आवश्यकता होती है। बचपन में अगर आवश्यकता से अधिक चीनी खाने की आदत पड़ जाए, तो भविष्य में स्मरण शक्ति के लिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेशनल जियोग्राफिक में प्रकाशित लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि बचपन में अत्यधिक मात्रा में चीनी का सेवन केवल दांतों या मोटापे तक सीमित नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इससे आगे के जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। शुरूआती उम्र में ज्यादा चीनी का सेवन व्यक्ति की स्मृति, व्यवहार और मेटाबॉलिज्म पर लंबे समय तक असर डालता है। रिपोर्ट के अनुसार, आज के बच्चे अनुशंसित सीमा से कई गुना अधिक चीनी का सेवन कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह विस्तार से बताया गया है कि बच्चों के लिए निर्धारित दैनिक चीनी सेवन सीमा लगभग 25 ग्राम यानी 6 चम्मच है, लेकिन अधिकतर बच्चे इससे दोगुना या तिगुना सेवन कर रहे हैं। इससे न केवल इंसुलिन प्रतिरोध और मोटापे का कारण बनता है, बल्कि भविष्य में हृदय रोग, टाइप-2 डायबिटीज के साथ मानसिक असंतुलन का खतरा भी बढ़ जाता है।

पैक्ड जूस और तैयार स्नैक्स में भी मौजूद रहती है छिपी हुई चीनी

- बाद के जीवन में शारीरिक ही नहीं, मानसिक संतुलन पर भी पड़ता है बड़ा असर
- जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए एक निश्चित मात्रा में होती है शुगर की जरूरत
- स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों के लिए निर्धारित दैनिक चीनी सेवन सीमा है 25 ग्राम
- भविष्य में इंसुलिन प्रतिरोध और मोटापे के साथ हृदय रोग का बढ़ जाता है खतरा

- हिडन शुगर से बच्चों को कम उम्र में ही उच्च शर्करा सेवन की पड़ जाती है आदत

ऐसी आदतों को बदलना कठिन

रिपोर्ट में यह समझाया गया है कि बचपन में अत्यधिक चीनी सेवन से जुड़ी आदतें एक साइकोलॉजिकल पैटर्न के रूप में विकसित हो जाती हैं। इन्हें बदलना अत्यंत कठिन होता है। वैज्ञानिकों ने इसे न्यूरल प्रोग्रामिंग ऑफ टेस्ट एंड बिहेवियर कहा है। मतलब दिमाग में बचपन से ही मीठे की तलब को स्थायी रूप से दर्ज कर देना। न्यू स्टडी से जुड़े कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइकोलॉजिस्ट डॉ. जॉन रॉजर्स के अनुसार, अधिक चीनी केवल वजन या दांतों की समस्या नहीं बढ़ाती, बल्कि यह मस्तिष्क में डोपामीन रिसेप्टर्स को असामान्य रूप से सक्रिय करती है।

भारत में बाल मोटापा की समस्या

इस विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) की रिपोर्ट बताती है कि शहरी भारत में 6 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे औसतन 32 से 45 ग्राम तक चीनी प्रतिदिन ले रहे हैं। यह अनुशंसित सीमा से लगभग दोगुना है। अधिकतर परिवारों को यह पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चों के नाश्ते के सीरियल, पैक्ड दूध, बिस्कुट और पेय पदार्थों में कितनी मथुरा में ऐडेड शुगर शामिल होता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा-

अगले वर्ष कर सकता हूं भारत की यात्रा

- भारत के प्रधानमंत्री मोदी को बताया अपना मित्र और अच्छा व्यक्ति

WASHINGTON @ PTI : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अगले वर्ष भारत की यात्रा कर सकते हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक सवाल पर कहा, वह (प्रधानमंत्री मोदी) मेरे दोस्त हैं, हम बात करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि मैं वहां आऊं। हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं जाऊंगा। मैंने वहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक शानदार यात्रा की थी। वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं फिर जाऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अगले साल भारत की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, हां, हो सकता है। गौरतलब है कि भारत नई दिल्ली में क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेता भाग लेंगे। इससे पहले 2024 का शिखर सम्मेलन विलमिंगटन (डेलावेयर) में आयोजित हुआ था। बहरहाल, भारत में होने वाले सम्मेलन की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। इस बीच, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि भारत ने रूस से खरीदारी बंद कर दी है।

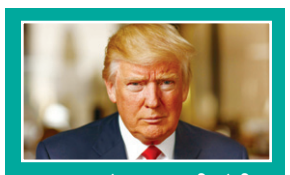

विधानसभा नियुक्ति घोटाले में 18 को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

RANCHI : विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की याचिका पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था। याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की पीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान दौरान समय मांगे जाने की वजह से न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि निर्धारित की। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले के सिलसिले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

BRIEF NEWS

तेलमच्चो हादसा : पांच शव मिले, छठे की तलाश

DHANBAD : कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दामोदर नदी में स्नान के दौरान हुए हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। बुधवार को धनबाद-बोकारो फोरलेन स्थित तेलमच्चो पुल के नीचे नौ युवक स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान नदी में अचानक तेज बहाव आने से सभी युवक बह गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि छह युवक लापता हो गए थे। घटना के बाद से ही राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। हादसे के दिन शाम करीब चार बजे एक युवक का शव बरामद किया गया था। इसके बाद गुरुवार को स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीन और शवों को नदी से निकाला गया था। वहीं, शुक्रवार सुबह एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाते हुए एक और शव बरामद किया है। इस तरह अबतक पांच शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक युवक की तलाश अब भी जारी है। भठिंडा फॉल से आए छह सदस्यीय गोताखोरों की टीम के सदस्य गंगाधर महतो और एनडीआरएफ टीम के कमांडर रविशंकर सरोज ने बताया कि वे लगातार तीन दिनों से सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह पानी में ऊपर तैरता हुआ शव दिखाई दिया, जिसे बाहर निकाला गया है। इधर, एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम गुरुवार की शाम धनबाद पहुंची थी। देर शाम डेढ़ घंटे तक अभियान चलाने के बाद अंधेरा बढ़ने पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। शुक्रवार सुबह से टीम फिर सक्रिय है और स्थानीय गोताखोरों के साथ मिलकर सर्च अभियान जारी रखे हुए है।

वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गान

PALAMU : वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुक्रवार को जिले में देशभक्ति से ओत-प्रोत माहौल देखने को मिला। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में वंदे मातरम का भव्य सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने एक साथ स्वर मिलाकर राष्ट्रभक्ति की गूंज से वातावरण को रोमांचित कर दिया। इस अवसर पर पलाश, कोयल और सोन की धरती पलामू देशप्रेम के स्वर से गूंज उठी। कार्यक्रम में आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, एनडीसी नीरज कुमार, डीईओ सौरभ प्रकाश सहित कई वरीय पदाधिकारी, शिक्षक, छात्र-छात्राएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में वंदे मातरम का गायन कर मां भारती को नमन किया। आईजी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा है। 1875 में पहली बार गाए गए इस गीत ने भारतवासियों में आजादी का संकल्प जगाया था। 150 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का प्रयास है। इसी क्रम में जिले के सभी प्रखंड, सरकारी कार्यालय, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मंत्री दीपक बिरुवा का तंज, पुत्र मोह में सियासी अंत की ओर बढ़ रहे चम्पाई

PHOTON NEWS CHAIBASA : राज्य के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा को फरार बताकर चाईबासा के आदिवासी संगठनों के घाटशिला पहुंचने के बाद मंत्री दीपक बिरुवा ने पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता चम्पाई सोरेन पर निशाना साधा है। चम्पाई सोरेन पर तीखा प्रहार करते हुए दीपक बिरुवा ने अफसोस जाहिर किया है। अपने 'एक्स' हैंडल के माध्यम से उन्होंने कहा है कि चम्पाई सोरेन की व्याकुलता व व्यथा बता रही है कि वे खुद की जमीर को मार कर अब सिर्फ पद और पुत्र के लिए राजनीतिक अस्तित्व की ओर बढ़ रहे हैं।

दीपक बिरुवा को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासी संगठनों ने चाईबासा सदर के विधायक दीपक बिरुवा को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल से हटाने की मांग उठाई गई है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में समाज के नेताओं ने कहा कि स्थानीय जनता समस्याओं से परेशान है, लेकिन मंत्री मिलते ही नहीं हैं। ये नो एंट्री लागू नहीं होने से मंत्री का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि नो एंट्री का समय निर्धारित नहीं रहने से अक्सर जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्कूल-कॉलेज के छात्र, अभिभावक से लेकर आसपास के ग्रामीण भी भारी वाहनों की तेज रफ्तार से आतंकित रहते हैं। इनका मानना है कि नो एंट्री लागू नहीं होने में मंत्री ही बाधक हैं। प्रेस वार्ता में मानकी मुंडा संघ के पदाधिकारी व हो महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष बामिया बारी, पूर्व अध्यक्ष रामाय पूर्ति, सचिव चंद्रमोहन बिरुवा, मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिन तामसोय, वरीय उपाध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र बोईपाई, ईचा-खरकई बांध संघ के सचिव सुरेश सोय, साधु बानरा, रियांस सामद आदि भी उपस्थित थे।

दीपक बिरुवा चम्पाई सोरेन

जनता जानती है। इस क्रम में बिरुवा ने चम्पाई सोरेन को सदैव सम्मानीय बताता हुए मौकापरस्त की भी संज्ञा दी है। इसके साथ ही कहा है कि आपको अनुकंपा पर नहीं बहुत अरमानों से मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन आप उस मयार्दा का पालन नहीं कर सके।

बहुत बड़ी हार, कर रही बाबूलाल का इंतजार : अपने एक्स हैंडल पर स्व. रामदास सोरेन की चिट्ठी कुछ पुरानी तस्वीरों को साझा करते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि रही बात घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तो आपको स्पष्ट बता दूं- बहुत बड़ी हार बाबूलाल का कर रही है इंतजार। इस क्रम में बिरुवा ने कहा है कि राज्य के तीन पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्री कोल्हान के अपने राजनीतिक पारी के आखिरी पायदान पर बेसब्री से आपकी राह देख रहे हैं, जो 14 नवंबर को स्वतः चरितार्थ हो जाएगा। यह एक्स संदेश उन्होंने चम्पाई सोरेन के अलावा झामुमो प्रमुख व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी को भी टैग किया है।

क्यों साधा निशाना : बता दें कि हाल ही में पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा में नो एंट्री को लेकर मंत्री दीपक बिरुवा का आवास घेराव करने जा रहे आदिवासी संगठनों के लोगों को तांबो चौक पर रोक दिया गया था। उसके बाद रात में लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने तथा आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई। तब चम्पाई सोरेन आंदोलनकारियों के समर्थन में आए और आंदोलन तेज करने की रणनीति के तहत मंत्री दीपक बिरुवा को फरार बताया गया। इसके साथ ही मंत्री बिरुवा को खोजने के लिए घाटशिला जाने का निर्णय लिया गया था।

इसके अनुसार चाईबासा से आदिवासी संगठनों के लोग विगत गुरुवार को- मंत्री लापता- लिखा बैनर-पोस्टर लेकर मंत्री दीपक बिरुवा को ढूंढते हुए घाटशिला पहुंचे थे। संभवतः इसे ही भाजपा प्रायोजित मानते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने चम्पाई सोरेन को निशाना बनाते हुए एक्स पर यह पोस्ट किया है।

धनबाद में ट्रेन से 78 जीवित कछुए बरामद, 7.8 लाख रुपये है कीमत

दून एक्सप्रेस की जनरल बोगी में तीन बोरों में भरकर कछुओं को रखा गया था

AGENCY DHANBAD : धनबाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ऑपरेशन डब्ल्यूआइएलईपी के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार तड़के योग नगरी ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13010) के महिला कोच से 78 जीवित कछुओं को बरामद किया है। बरामद किए गए कछुओं का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 7.8 लाख रुपये बताया जा रहा है।

बरामद कछुओं के साथ आरपीएफ के जवान

जानकारी के अनुसार वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त, धनबाद के निर्देश पर तैनात आरपीएफ की टास्क टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दून एक्सप्रेस की महिला कोच में भारी मात्रा में वन्यजीवों की तस्करी की जा रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम प्लेटफॉर्म संख्या 02 पर पहुंची और ट्रेन के आगमन पर महिला कोच की तलाशी ली। जांच के दौरान सीट के नीचे से कपड़े के छह लावारिस थैले बरामद हुए। जब टीम ने आसपास की महिला यात्रियों से पूछताछ की तो किसी ने भी उन थैलों पर दावा नहीं किया। संदेह होने पर थैलों को खोला गया। जिनमें जूट के बोरे में बंद 78 जीवित इंडियन फ्लैपशेल प्रजाति के कछुए पाए गए। आरपीएफ ने सभी कछुओं को जब्त कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई शुरू की और तत्काल वन विभाग को सूचित किया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बरामद कछुओं को वन क्षेत्र पदाधिकारी धनबाद को सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सफल अभियान वन्यजीव तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रामगढ़ में ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

पत्रकारों को मामले की जानकारी देते एसडीपीओ गौरव गोस्वामी (सबसे बाएं)

RAMGARH : जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। गांजा, डोडा, नशीले इंजेक्शन के बढ़कर ब्राउन शुगर की तस्करी होने लगी है। पतरातु क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करते दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पतरातु एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने संवाददाता सम्मेलन कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भुरकुंडा इलाके में छापेमारी की गई। दो मुहानी रिवर साइड के पास एक बोलेरो (जेएच 01 एएच 1869) को रोका गया। पुलिस को देखकर गाड़ी का चालक और एक अन्य सवार व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ा और तलाशी ली। पकड़े गए तस्करों में कौड़ी बरकाकाना निवासी राजेश कुमार बेदिया और चैनगड्डा निवासी महफूज आलम उर्फ राजन शामिल हैं। उनके पास से 9 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है।

दूसरी शादी से नाराज पहली पत्नी ने सहयोगियों से मिलकर की थी पति रंजीत की हत्या, दो गिरफ्तार

खूंटी पुलिस ने किया खुलासा, हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद, दो अन्य की तलाश

AGENCY KHUNTI : खूंटी के गिरजा टोली स्थित महावीर कॉलोनी में रहने वाले रंजीत महतो उर्फ टुना नामक युवक की एक सप्ताह पूर्व धारदार हथियार से गला काटकर की गई हत्या मामले में पुलिस ने मृतक की पहली पत्नी सुगी देवी और उसके एक रिश्तेदार सोनू महतो को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। गिरफ्तार आरोपितों ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि पहली पत्नी के रहते रंजीत महतो ने जब दूसरी शादी कर ली तो गुस्से में आकर पहली पत्नी ने पति रंजीत महतो की हत्या की योजना बना डाली और अपने रिश्तेदार सोनू महतो एवं अन्य दो लोगों के साथ मिलकर गत 31 अगस्त को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक स्टील का भुजाली (बड़ा चाकू), एक बोतल में पेट्रोल जैसा तरल पदार्थ और घटना के समय आरोपियों की ओर से पहने गए कपड़ों के जले हुए अवशेष को बरामद कर लिया है। यह जानकारी खूंटी एसडीपीओ वरुण रजक ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बताया गया कि इस घटना में शामिल अन्य दो आरोपित फिलहाल फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उल्लेखनीय है कि मूल रूप से सोनाहातू का निवासी रंजीत महतो उर्फ टुना का शव गत 31 अक्टूबर को शहर के कदमा बस्ती से शांतिपुर अमृतपुर जाने वाली सड़क पर स्थित तालाब के पास झाड़ियों से बरामद किया गया था। इस संबंध में मृतक की दूसरी पत्नी रेणु देवी के लिखित आवेदन पर खूंटी थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहली पत्नी सुगी देवी और उसकी बहन के बेटे सोनू महतो को पकड़ कर जब उससे पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। गिरफ्तार सोनू महतो का अपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ खूंटी थाना में जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने का एक मामला (कांड संख्या 152/ 11) दर्ज है।

घटना की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी

पशु धन विकास योजना के लाभुकों की सूची पर चर्चा

KHUNTI : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त आर रॉनिटा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26) अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों से प्राप्त प्रखंड स्तरीय समिति ने अनुशंसित लाभुकों की सूची पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक में बकरा, सुकर, ब्रायलर कुक्कुट, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट, बत्तख चूजा, जोड़ा बैल वितरण, गाय और भैंस, डेयरी फार्मिंग, हस्त चालित चैफ कटर, वर्मी कंपोस्ट, डीप बोरिंग, मिल्किंग मशीन, पनीर और खोवा मेकिंग यूनिट सहित भिन्न घटकों के लाभुकों की सूची की समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद जिला स्तरीय समिति ने प्रखंडों से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर लाभुकों की सूची को अनुमोदित किया। अनुमोदित लाभुकों को पशुपालन और गव्य विकास विभाग की ओर से 75 से 90 प्रतिशत अनुदान पर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और पशुधन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

खूंटी में 'आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम 18 से

AGENCY KHUNTI : आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी आर. रॉनिटा की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने राज्य सरकार से प्राप्त निदेशों के आलोक में 11 से 15 नवंबर तक चलने वाले सभी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस का रजत वर्ष प्रदेश एवं जिले के लिए अत्यंत गर्व का अवसर है।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक करतीं उपायुक्त

अतः सभी कार्यक्रमों का आयोजन भव्य, आकर्षक और सुव्यवस्थित तरीके से हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागों को अपने-अपने दायित्वों के प्रति पूरी सक्रियता और संवेदनशीलता से कार्य करने को कहा। बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। 11 नवंबर से ही विभिन्न गतिविधियों की शुरूआत होगी। इसमें 'रन फॉर झारखंड', प्रचार वाहन के माध्यम से जनजागरूकता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, निबंध, चित्रांकन तथा क्विज प्रतियोगिताएं शामिल रहेंगी। पर्यटन स्थलों तक साइकिल रैली और ट्रेकिंग जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि 15 नवंबर को उलिहातू में आयोजित कार्यक्रम को इस वर्ष राजकीय बिरसा महोत्सव के रूप में विशेष रूप से मनाया जाएगा।

लोहरदगा में 13 पुलिस अफसर इधर से उधर, सेन्हा के थानेदार लाइन हाजिर

किस्को के थाना प्रभारी को मिला जोबांग का प्रभार, अजीत बने कुडू के नए थानेदार

PHOTON NEWS LOHARDAGA : लोहरदगा जिले में पुलिस विभाग ने बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार, जिले के 13 पुलिस पदाधिकारियों के स्थान में बदलाव किया गया है। इसमें एसपी ऑफिस की डीसीबी शाखा में तैनात अजीत कुमार को कुडू का थानेदार बनाया गया है। वहीं, कुडू के थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह को लोहरदगा थाने में अवर निरीक्षक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। इसमें एकमात्र किस्को के थानेदार सुमन मिंज को दूसरे थाना जोबांग का नया थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि सेन्हा के थाना प्रभारी वारिश हुसैन का लाइनक्लोज किया गया है। इनके स्थान पर सेन्हा थाना प्रभारी की जिम्मेदारी भंडरा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक नीरज झा संभालेंगे। जोबांग के थाना प्रभारी हर्षवर्धन कुमार सिंह को सिविल कोर्ट में प्रतिनियुक्त किया गया है। अभियोजन शाखा के प्रभारी मानस कुमार साधु को किस्को थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह सेरेंगदाग थाना प्रभारी रामाशीष यादव को कुडू थाना में पदस्थापित किया गया है। सिविल कोर्ट से नरेश कुमार यादव को सेरेंगदाग का थाना प्रभारी बनाया गया है। महिला थानेदार जेनी सुधा तिग्गा को सीसीआर के मीडिया सेल, डायल-112 में पदस्थापित किया गया है। वहीं महिला थाना की पुलिस अवर निरीक्षक बिनीता हेम्ब्रम को महिला थाना का प्रभारी बनाया गया है। एसटी-एससी, अहातु थाना प्रभारी अमित कुमार मुर्मू को लोहरदगा थाना में पदस्थापित किया गया है। इसके साथ एसपी ऑफिस की हिंदी शाखा के प्रभारी लक्ष्मण हांसदा को एसटी-एससी, अहातु थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

मुसीबत चाईबासा में एचआईवी पॉजिटिव ब्लड मामले का साइड इफेक्ट, थैलेसीमिया पीड़ित के परिजन परेशान

हजारीबाग के ब्लड बैंकों में रक्त की भारी किल्लत

PHOTON NEWS HAZARIBAG : हजारीबाग में जरूरतमंद मरीजों को खून के संकट से जूझना पड़ रहा है। इसकी वजह रक्तदाताओं की संख्या में कमी मानी जा रही है। इसके साथ ही इसे चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ा दिए जाने का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। बताया जाता है कि चाईबासा की घटना के बाद राज्य सरकार की ओर से नया नियम लागू कर दिए जाने के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब बिना रक्तदान के ही जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने का प्रावधान कर दिया गया है। उसके बाद से यहां रक्तदाताओं की कमी हो गई है। रक्तदान नहीं होने की स्थिति में जिले के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित ब्लड बैंक समेत निजी ब्लड बैंकों में भी खून की भारी किल्लत हो गई है।

रक्तदाता आगे नहीं आए तो बढ़ेगा संकट

हजारीबाग के निजी ब्लड बैंकों में भी कमोबेश यही स्थिति है। सुबह से दो महिलाएं अपने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड बैंक में रक्त का इंतजार कर रही थीं, लेकिन उन्हें अभी तक रक्त नहीं मिल पाया है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि रक्तदाता आगे नहीं आते हैं, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।

खाली हाथ लौट रहे कई जरूरतमंद

स्थिति यह है कि कई मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, तो कुछ लोगों को लंबे इंतजार के बाद रक्त मिल पा रहा है। थैलेसीमिया जैसे नियमित रक्त की आवश्यकता वाले मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि पहले 'खून के बदले खून' देने की व्यवस्था थी। अब किसी भी जरूरतमंद को रक्त के लिए रक्तदाता लाने की बाध्यता नहीं है। जानकार बताता हैं कि राज्य सरकार के इस फैसले का उद्देश्य जनहित में था, लेकिन रक्तदाताओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस वजह से जिले के ब्लड बैंकों में रक्त का स्टॉक लगभग खाली हो गया है।

ब्लड बैंक में मात्र 20 यूनिट रक्त

ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ. नीरज कुमार ने बताया कि दो दिन पहले तक बैंक में लगभग 100 यूनिट रक्त उपलब्ध था, जो अब घटकर केवल 20 यूनिट रह गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो कुछ ही घंटों में एक भी यूनिट रक्त नहीं बचेगा। रक्त संकट के कारण कई मरीजों को जीवनरक्षक उपचार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिजन पिछले दो दिनों से रक्त की तलाश में ब्लड बैंक और निजी नर्सिंग होम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है।

BRIEF NEWS

झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप 15 से कमेटी गठित

RANCHI : सिकोकई कराटे इंटरनेशनल झारखंड और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में 15 नवंबर से झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। रांची के बिशप स्कूल में होने वाली चैंपियनशिप के सफल आयोजन को लेकर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के तकनीकी निदेशक रेंसी सुनील किस्पोट्टा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का गठन किया गया। कमिटी में निदेशक रेंसी सुनील किस्पोट्टा, अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा, उपाध्यक्ष मोहिनी रितिका टोप्पो, सचिव राकेश तिर्की, उमाशंकर महतो, संयुक्त सचिव रवि कुमार सिंह, स्वस्तिका तरफदार, सदस्य सुदेश कुमार महतो, दीपा, बिनीता लिंडा, एनी कोनगाड़ी, रितिका तिग्गा, आरती टोप्पो, दीपशिखा तिग्गा, प्रतिभा तिग्गा और आयुष सांगा बनाए गए है। सुनील किस्पोट्टा ने कहा कि ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना और खेल को सुचारू रूप से संचालित कर प्रतियोगिता का सफल आयोजन करना है। सभी पदाधिकारियों को उनके कार्यभार सौंप दिए गए हैं।

साईं करुणा और धुर्वा ने जीता मैच, खिलाड़ियों का रहा शानदार प्रदर्शन

RANCHI : शुक्रवार को साईं करुणा प्रीमियर लीग में दो

मुकाबले खेले गए। पहले मैच में साईं करूणा ने अरुणोदय ए को 4 विकेट से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए अरुणोदय ए ने 155 रन बनाए। जवाब में साईं करुणा ने 19.3 ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अरुणोदय ए के तरफ से कार्तिक ने 48 रन बनाएं और सागर ने 2 विकेट लिए। वहीं दूसरे मैच में साईं धुर्वा ने अरुणोदय बी को 1 विकेट से हराया। अरुणोदय बी 20 ओवर में 148 रन ही बना पाई। साईं धुर्वा ने 19.4 ओवर में जीत हासिल कर ली। अरुणोदय बी के तरफ से प्रदुम्न ने 47 और आदर्श ने 43 रनों की पारी खेली। साईं धुर्वा के तरफ से प्रखर ने 47 रन की पारी खेली।

शिक्षक नियुक्ति पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

RANCHI : सहायक आचार्य के लिए सोशल स्टडीज (क्लास छह से आठ) नन पारा कैटेगरी के शेष रिक्त पदों पर रिजल्ट जारी करने को लेकर उमाकांत महतो एवं अन्य की याचिका की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को हुई। मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन से उक्त विषय के सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स स्टेटमेंट, अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का मार्क्स प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

जिन गांवों तक सड़क नहीं पहुंची, वहां कराया जाए निर्माण : रंजना चोपड़ा

- नीति आयोग की सचिव ने कई राज्यों के पदाधिकारियों के साथ सुपर 60 सेमिनार में लिया भाग
- 2018 में पीवीटीजी कल्याण के लिए शुरू की गई योजना का दिख रहा सकारात्मक असर
- सीएम हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में सरकार कई नवाचारों पर कर रही काम

PHOTON NEWS RANCHI : नीति आयोग की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर आदिम जनजातीय समूह) क्षेत्रों में हाउसहोल्ड सैचुरेशन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन गांवों तक सड़क नहीं पहुंची है, वहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मनरेगा के माध्यम से कार्य कराया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सके। गांवों तक ऐसी कनेक्टिविटी विकसित की जानी चाहिए कि लोगों के दरवाजे से अस्पताल, स्कूल और शहर तक वाहनों की सहज पहुंच संभव हो। शुक्रवार को वह पीवीटीजी समुदायों के विकास पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रही थीं। रंजना चोपड़ा ने बताया कि 2018 में पीवीटीजी कल्याण के लिए शुरू की गई योजना का अब सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों में हर घर नल योजना, सड़क निर्माण और विद्युतीकरण के कार्य सैचुरेशन मोड में पूरे किए जा चुके हैं। झारखंड समेत कई राज्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि 100 लोगों से कम आबादी वाले टोलों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही आदिम जनजाति की महिलाओं को काम के दौरान राहत देने के लिए क्रेच (बच्चों की देखभाल केंद्र) खोले जाने की योजना भी बनाई जा रही है।

नीति आयोग की सचिव ने झारखंड के पीवीटीजी क्षेत्रों में हुए कार्यों और शेष कार्यों का विस्तृत डेटा तैयार करने का निर्देश दिया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस क्षेत्र में कौन सी योजना लागू करने की जरूरत है। नीति आयोग के अपर सचिव और मिशन डायरेक्टर रोहित कुमार ने कहा कि पीवीटीजी योजना ऐसी पहल है, जिसके माध्यम से आदिम जनजाति समुदायों के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पिछड़ी आदिवासी कम्युनिटी निवास करती है, वहां विकास कार्यों के माध्यम से स्वावलंबन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीवीटीजी योजना केवल बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति तक सीमित नहीं है।

चुनौतियों के बावजूद हुआ बेहतर कार्य

झारखंड में पीवीटीजी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से राज्य के दुर्गम इलाकों में विकास की नई बयार बह रही है। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में योजना एवं विकास सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि राज्य की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद झारखंड ने आदिम जनजातीय समुदायों के विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य सरकार पीवीटीजी समुदायों के समग्र विकास के लिए कई नवाचारों पर काम कर रही है।

मिसाल कायम कर रहीं दीदियां

झारखंड में पीवीटीजी समुदाय के समग्र विकास की दिशा में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दीदी की दुकान नई मिसाल कायम कर रही है। योजनाओं के संचालन से जुड़ी चुनौतियों और उपलब्धियों पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि किस तरह लखपति दीदी पहल राज्य में ग्रामीण आजीविका की सशक्त कहानी लिख रही है। दीदी की दुकान योजना के तहत दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में डेली खपत होने वाली वस्तुओं की दुकान शुरू की गई हैं। इन दुकानों की शुरूआत 30 हजार से 1 लाख रुपये तक के लोन से की गई थी। वर्तमान में राज्य के विभिन्न प्रखंडों में कुल 1276 दीदी की दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें से 386 गांव ऐसे हैं, जहां पहली बार कोई दुकान खुली है। जिससे घर के पास सामान मिल रहा है। औसतन एक दीदी की दुकान से हर महीने लगभग 9,100 रुपये की आय हो रही है। इसके साथ ही राज्य के 113 गांवों में 'दीदी का ढाबा' भी शुरू किया गया है। विशेष रूप से 'डाकिया योजना' जैसी पहल ने दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है।

मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए विभाग ने की तैयारी

150 हॉस्पिटल मैनेजरों के हाथों में होगी सरकारी अस्पतालों की कमान

- एक महीने के अंदर सभी मैनेजरों की हॉस्पिटलों में की जाएगी तैनाती
- प्राइवेट हॉस्पिटलों जैसी सुविधाएं देने की स्वास्थ्य विभाग ने बनाई योजना
- अस्पतालों में कमियों को दूर करने और व्यवस्था दुरुस्त रखने का करेंगे काम
- हर दिन लाखों मरीज झारखंड के सरकारी अस्पतालों में करा रहे इलाज

VIVEK SHARMA RANCHI : झारखंड के सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेट हॉस्पिटलों की तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अब इलाज के लिए आने वाले मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर सीएचसी और पीएचसी में भी बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। इससे मरीजों को छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए मैनेजरों के हाथों में कमान सौंपी जा रही है, ताकि मरीजों को वर्ल्ड क्लास सुविधा घर के पास ही मिल सके। नेशनल हेल्थ मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि इलाज के दौरान होने वाली अव्यवस्था, लंबी कतार, दवाओं की कमी और प्रबंधन की समस्याओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार 150 प्रशिक्षित हॉस्पिटल मैनेजर नियुक्त कर रही है, जो अस्पतालों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। विभाग का मानना है कि जब अस्पताल का संचालन प्रोफेशनल तरीके से होगा, तो मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा। अगले एक महीने के भीतर सभी 150 मैनेजरों की राज्यभर के अस्पतालों में तैनाती कर दी जाएगी।

समन्वय बनाकर समस्याओं का समाधान : हॉस्पिटल में इन मैनेजरों की जिम्मेदारियां तय होंगी। हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के पहुंचने के साथ इलाज शुरू कराना होगा। ये लोग दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। हॉस्पिटल में काम करने वाले विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर समस्याओं का समाधान भी करेंगे। डॉक्टर और स्टाफ की उपलब्धता पर भी नजर रखेंगे और विभाग को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। अस्पताल की सफाई और सुविधाओं की नियमित समीक्षा के साथ सरकार की आयुष्मान योजना की भी जानकारी मरीजों को देंगे। इसके अलावा मरीजों को एंबुलेंस भी उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।

सरकारी में प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधा

अभियान निदेशक ने कहा कि सरकारी अस्पतालों की छवि भीड़भाड़, देरी और रेफरल वाली न रहे। विभाग एक ऐसा सिस्टम लागू कर रहा है, जिसमें मरीजों के इलाज को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ महीनों में मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जैसी क्वालिटी सर्विस मिलेगी। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन लाखों मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं। अधिकतर अस्पतालों में प्रबंधन की कमी के कारण डॉक्टरों पर भी प्रशासनिक काम का दबाव होता है। अब डॉक्टर केवल इलाज करने पर फोकस करेंगे।

रांची सदर में हैं एचएम

सुपर स्पेशलिटी सदर हॉस्पिटल, रांची में पहले से ही हॉस्पिटल मैनेजर काम कर रहे हैं। इससे मैनपावर से लेकर सफाई व्यवस्था तक दुरुस्त है। इसके अलावा हर फ्लोर पर मरीजों को सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभियान निदेशक ने बताया कि आज सदर हॉस्पिटल, रांची देश में नंबर एक है। इसी तरह की व्यवस्था सभी सरकारी हॉस्पिटलों में दी जाएगी।

कृषि मंत्री ने वितरित की जंगली जानवरों से हुए फसल नुकसान की मुआवजा राशि

मुआवजा राशि से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट का वितरण करतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की

PHOTON NEWS RANCHI : कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को आदिवासी रीति-रिवाज, पूजा-पाठ में जंगल के महत्व को समझना होगा। कई बार यह देखा जाता है कि पेड़ की टहनियों को घर लाने पर भी ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। यह कार्य जनता के साथ अन्याय है। वन संरक्षण कानून के तहत ग्रामीणों को मिलने वाले हक को कोई छीन नहीं सकता। मंत्री शुक्रवार को रांची वन रोपण प्रक्षेत्र, बेड़ो अंतर्गत जंगली जानवरों से हुए फसल और मकान क्षति का मुआवजा वितरण सह पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सच्चाई है कि झारखंड में कटते जंगल के कारण मनुष्य और जानवरों के बीच तनाव बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का प्रकोप इसी का नतीजा है। जंगली हाथी, लकडबग्घा और भालू के हमले इसके उदाहरण हैं। हाथियों की ओर से आए दिन किसानों के फसलों, मकान को नुकसान पहुचाने की बातें सामने आती है। मौके पर उन्होंने बेड़ो, इटकी एवं लापुंग प्रखंड के भुक्तभोगी परिवारों के बीच मुआवजा राशि से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट का वितरण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मुआवजा राशि भुक्तभोगी परिवार को हुए नुकसान और उनके दर्द को कम करने में मददगार साबित होगा। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि जंगल है तो जमीन है और जमीन है तो जीवन है। जीवन के साथ परम्परा और संस्कृति जुड़ी हुई है। कभी जहां जंगली जानवर रहा करते थे, आज वहां मनुष्यों की आबादी का दखल है।

शिशु संरक्षण दिवस पर सामूहिक जिम्मेदारी और जागरूकता का आह्वान, एक्सपर्ट बोले-

नवजात को लेकर जब तक समाज नहीं होगा जागरूक, अपराधों पर अंकुश लगाना कठिन

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को शिशु संरक्षण दिवस पर सहभागिता : सुरक्षित शिशु अभियान कार्यक्रम का आयोजन जिला बाल संरक्षण इकाई रांची द्वारा आश्रयणी फाउंडेशन (पालोना अभियान) के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य नवजात शिशुओं की सुरक्षा, देखभाल और जीवन अधिकार को लेकर समाज व संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाना था। कार्यक्रम की थीम नवजीवन की रक्षा, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी रखी गई थी। इस दौरान शिशुओं के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे परित्याग, शिशुहत्या, शिशु तस्करी और यौन शोषण की रोकथाम पर गहन चर्चा की गई। रांची के बाल संरक्षण अधिकारी वेद प्रकाश तिवारी ने कहा कि शिशु संरक्षण केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का विषय है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक इन अपराधों पर अंकुश लगाना कठिन होगा। उन्होंने पालोना अभियान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल राज्य और देश दोनों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है। पालोना अभियान की राज्य प्रमुख संगीता कुजारा ने अभियान के तहत की जा रही गतिविधियों जैसे डेटा संग्रह, जनजागरूकता, मीडिया वकालत और प्रशिक्षण पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पालोना, आश्रयणी फाउंडेशन की एक सामाजिक पहल है जो शिशुहत्या और असुरक्षित परित्याग को रोकने के लिए समर्पित है।

जीवन में तनाव भी कम करते हैं खेल : आईजी

RANCHI : रांची के कांके रोड स्थित पुलिस लाइन में शुक्रवार से तीन दिवसीय दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि रांची जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) मनोज कौशिक के साथ रांची के वरिय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन तथा सिमडेगा और खूंटी के पुलिस अधीक्षकों ने बैलून उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए आईजी मनोज कौशिक ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, बल्कि तनाव को भी कम करते हैं।। उन्होंने कहा कि तनाव पुलिस अधिकारियों के लिए एक चुनौती है, लेकिन इससे निपटने के लिए फिट रहना जरूरी है।

देर से ही सही, लेकिन मेरे सुझाव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया अमल : बाबूलाल मरांडी

PHOTON NEWS RANCHI : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष-सह-नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर नए कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर से ही सही, लेकिन उन्होंने हमारे सुझाव पर अमल किया। झारखंड के दागी, विवादास्पद और अपराधी किस्म के रिटायर्ड अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा लेकर उन्हें हटाया। इसके लिए धन्यवाद। साथ ही कहा कि भगवान का शुक्र है कि इन्हें आपने बाहर का रास्ता दिखाया वरना आगे आपको और झारखंड के लोगों को क्या-क्या देखने सुनने और झेलने पड़ते। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रूप में हमने न सिर्फ आपकी सरकार की अवैध नियुक्तियों और मनमानी पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी स्पष्ट कहा था कि राज्य के डीजीपी पद पर बैठे अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध है। हमने बार-बार आपको आगाह किया कि इस पर शीघ्र कार्रवाई करें। अब जाकर आपकी नींद टूटी और आपने मजबूरन अनुराग गुप्ता से इस्तीफा मांग ही लिया। बाबूलाल ने कहा कि अब आप एक और सलाह मान लीजिए कि आपकी सरकार की नीति तो शुरू से ही रही है जितना बड़ा दुराचारी, उतना बड़ा पदाधिकारी। उसी परंपरा को बनाए रखते हुए, अनुराग गुप्ता को किसी और सम्मानित पद से तुरंत नवाज दीजिए। इससे आप दोनों के हित भी सुरक्षित रहेंगे और आपके बीच के सारे राज भी राज ही बने रहेंगे। कहीं ऐसा न हो कि आदतन ये व्यक्ति घर का भेदी-लंका ढ़ाहे की तर्ज पर आपकी लंका में आग लगाने का काम शुरू कर दे।

एक्शन रांची नगर निगम में अधिकारियों ने की बैठक, वेंडर मार्केट का किया निरीक्षण

अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं, होगी कार्रवाई

कब्जा करने वालों को चेतावनी

निरीक्षण के दौरान अपर प्रशासक ने अनाधिकृत कब्जाधारियों को 24 घंटे में स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़क पर दुकान लगाने वालों का आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि मार्केट की स्वच्छता, सुरक्षा और लाइट व्यवस्था सुचारू रखी जाए। वहीं इनफोर्समेंट टीम के साथ बैठक में उन्होंने शहर को जाममुक्त व अतिक्रमणमुक्त बनाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। सीएनडी वेस्ट फेंकने वालों और गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश उन्होंने दिया। इसके अलावा निगम की टीम ने 6 अवैध होर्डिंग्स हटाई।

राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा

राज्य स्थापना दिवस को लेकर रांची नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 15-16 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के पूर्व 11 से 14 नवंबर तक विभिन्न आयोजन होंगे। जिसमें रन फार झारखंड, सांस्कृतिक नृत्य, नो योर टूरिस्ट प्लेस और वॉल पेंटिंग में लोग भाग ले सकते हैं। संजय कुमार ने निर्देश दिया कि साफ-सफाई, पेयजल, पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के सभी कार्य समय पर पूर्ण हों।

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को रांची नगर निगम में अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। इसमें राजस्व वसूली, स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने के अलावा झारखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी हाल में अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व शाखा की बैठक में अपर प्रशासक ने राजस्व संग्रहण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बकाएदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बड़े बकाएदारों को अंतिम नोटिस जारी कर भुगतान न करने की स्थिति में कठोर कदम उठाए जाएं। साथ ही सभी जोन में ट्रेड लाइसेंस जांच के लिए सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बिना वैध लाइसेंस वाले व्यवसायियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सैफ के अंतर्गत री-असेसमेंट और नई संरचनाओं की जांच तेजी से पूरी करने को कहा। विशेष रूप से 20,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों की वास्तविकता की जांच कर अतिरिक्त डिमांड तैयार करने का निर्देश दिया गया। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक हुई। जिसमें गीला और सूखा कचरा के सेपरेशन पर जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि झिरी स्थित गेल के 150 टन प्रतिदिन कैपेसिटी वाले सीबीजी प्लांट में रोजाना 150 टन गीला कचरा चाहिए। जिसका इस्तेमाल ऊर्जा व खाद उत्पादन में होता है। आरडब्लूए के प्रतिनिधियों ने निगम की पहल की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज को होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़ा जाए।

सौहार्द बनाए रखने के लिए ग्रामीणों ने की बैठक, शांति समिति गठित

PHOTON NEWS BERO : शुक्रवार को प्रखंड के करांजी गांव के टिकरा में विशेष बैठक हुई, जिसमें ग्रामीणों ने आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर चर्चा की। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हाल के दिनों में छोटी-छोटी बातों को लेकर समाज में सांप्रदायिक रंग चढ़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो शासन-प्रशासन के साथ-साथ गांव की एकता और शांति के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने बताया कि गैर-मजरुआ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और दखल को लेकर भी समय-समय पर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। बैठक में बतलाया गया कि गांव में शांति

समिति का गठन किया गया है, जिसमें सभी समाजों के बुद्धिजीवी व जिम्मेदार लोग शामिल हैं। समिति का उद्देश्य आपसी विवादों को संवाद के माध्यम से सुलझाना और गांव में शांति व सद्भाव बनाए रखना है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए समाजसेवी बबलु खान ने कहा कि अप्रिय घटना से गांव बदनाम होगा, तो गांव के सभी लोग बदनाम होंगे, अगर गांव में किसी प्रकार का अप्रिय घटना तो शांति समिति के सदस्यों को खबर करें, त्वरित कार्यवाई किया जाएगा।

रांची में शुरू हुई 7वीं डेंटल कॉन्फ्रेंस, आज जुटेंगे देशभर के डेंटिस्ट

RANCHI : इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) रांची शाखा द्वारा 7वीं झारखंड स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को जेई डुंजीभॉय एकेडमिक एंड रिसर्च ब्लॉक रिनपास, कांके में शुरू हो गई। तीन दिवसीय यह सम्मेलन 9 नवंबर तक चलेगा। इसमें देशभर से डेंटल एक्सपर्ट और रिसर्च स्कॉलर शामिल हो रहे हैं। इस दौरान एंडोडोंटिक्स, मेडिको लीगल आस्पेक्ट, आथोडोंटिक्स, लेजर डेंटिस्ट्री, ओरल कैंसर, लोकल एनेस्थेसिया और टेंपरोमैंडिबुलर जाइंट डिसआर्डर पर चर्चा होगी।

अवैध बालू ढुलाई का विरोध करने पर युवक को ट्रैक्टर से कुचला, मौत

ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन, वाहन जब्त, चालक फरार

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध बालू का धंधा अब खूनी रूप ले रहा है। जैतगढ़ ओपी थाना क्षेत्र में ऐसे ही एक मामले में अवैध रूप से बालू खनन और ढुलाई का विरोध करने पर एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मुंडाई गांव निवासी दीपक प्रधान के रूप में हुई है।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने लाश सड़क पर रख विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए चाईबासा स्थित सदर अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में जगन्नाथपुर के थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

दीपक प्रधान का शव ● फोटोन न्यूज

बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी

स्थानीय लोगों का कहना है कि बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है, जिसका विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। लेकिन बालू माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बालू की तस्करी कर रहे हैं। इस पर ना तो पुलिस कार्रवाई करती है और ना ही खनन विभाग। जिस कारण बालू माफिया की मनमानी जारी है। सरकार की गलत नीतियों के कारण बालू के अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है।

फुटबॉल मैच देखकर लौट रहे युवक की गला रेतकर हत्या

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में सोहराय-बांदना पर्व के अवसर पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच देखकर लौट रहे एक युवक की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सोमनाथ हेम्ब्रम उर्फ धोनी हेम्ब्रम, पिता सुरेन हेम्ब्रम, निवासी छोटा रायकमन गांव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार घटना रविवार रात की है। सोमनाथ हेम्ब्रम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच देखकर लौट रहा था। इसी दौरान छोटारायकमन गांव के ताड़ीसाई टोला से धानसारी जाने वाली मुख्य सड़क पर अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। इससे सोमनाथ हेम्ब्रम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए चाईबासा स्थित सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि सोमनाथ हेम्ब्रम का किसी से कोई विवाद नहीं था। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। हत्यारों की तलाश की जा रही है।

जमशेदपुर में भाजपा 15 से मनाएगी 'वंदे मातरम' पर राष्ट्रीय उत्सव

JAMSHEDPUR : भाजपा, जमशेदपुर महानगर 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में 15 नवंबर से मनाएगी। शुक्रवार को साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने बताया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर साकची स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके पश्चात प्रतिमा स्थल पर 150 से अधिक नागरिकों एवं वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का संपूर्ण गायन किया जाएगा। सुधांशु ओझा ने बताया कि 'वंदे मातरम' वर्ष 1875 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था, जिसका प्रथम वाचन 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में किया था। वर्ष 1950 में प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया। प्रेस वार्ता में जमशेदपुर महानगर के महामंत्री अनिल मोदी, उपाध्यक्ष सह कार्यक्रम के संयोजक बबुआ सिंह, मीडिया प्रभारी प्रेम झा समेत उज्ज्वल सिंह एवं किशोर ओझा भी मौजूद रहे।

धतकीडीह तालाब से युवक का शव बरामद, जांच जारी

टीएमएच परिसर में खड़े परिजन ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : बिस्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडीह तालाब में शुक्रवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय दीपक नाग के रूप में हुई है, जो धतकीडीह के मुखी बस्ती का निवासी था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दीपक को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद उसे तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि दीपक तालाब में कैसे डूबा, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि दीपक मेहनत-मजदूरी करता था, वह किसी प्रकार का नशा नहीं करता था और उसका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर है। धतकीडीह मुखी समाज के महासचिव संजय कंसारी अस्पताल पहुंचे और प्रशासन और टाटा स्टील प्रबंधन से तालाब की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि इस तालाब में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए यहां स्थायी रूप से गार्ड की नियुक्ति की जाए और चारों ओर सुरक्षा जाली लगाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

समाचार सार

समाहरणालय में हुआ वंदे मातरम का सामूहिक गान

SERAIKELA : सरायकेला-खरसावां जिले के समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को वंदे मातरम का गायन हुआ। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने भी यह गीत गाया, उनके साथ उपविकास आयुक्त रीना हांसदा व अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार के अलावा सामूहिक गान में जिला प्रशासन के लगभग सभी पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। यह आयोजन प्रखंड, अंचल व पंचायत कार्यालयों में भी हुआ।

जादूगोड़ा में अर्जुन मुंडा का रोड शो, मांगा समर्थन

GHATSILA : घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा और झामुमो नेताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जोर-शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच, शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जादूगोड़ा में रोड शो किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान अपने संबोधन में अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड की जनता इस निकम्मी, भ्रष्ट और वादाखिलाफी वाली हेमंत सरकार से तंग आ चुकी है। छह साल में न तो कोई विकास हुआ, न ही रोजगार मिला। कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य घोटालों, भ्रष्टाचारियों और माफिया के हवाले हो गया है। जादूगोड़ा मंडल के चुनाव प्रभारी सुरेश साव ने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है और इस उपचुनाव में उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। भाजपा एकतरफा चुनाव जीत रही है, इसलिए विरोधी हताश हो गए हैं। इस मौके पर गुरुचरण रजवार, चंचल दास, रीना महली, मनोज प्रताप, विक्रम सिंह, रोहित अग्रवाल, पिंटू मंडल, संदीप कुमार, तन्नुश्री, वरुण सिंह, उज्ज्वल गुप्ता, ओंकार दुबे, अशोक विश्वकर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता व जनता की उपस्थिति रही।

एलबीएसएम में डिजिटल अवेयरनेस कार्यशाला शुरू

JAMSHEDPUR : करनडीह स्थित एलबीएसएम कॉलेज में शुक्रवार को तीन दिवसीय डिजिटल अवेयरनेस, एम्पावरमेंट एवं उद्यमिता कार्यशाला शुरू हुई। कॉलेज की आईक्यूएसी के नेतृत्व तथा ई-डिजिटल इंडिया के सहयोग से हो रही कार्यशाला 6 से 8 नवंबर तक चलेगी। कार्यशाला में शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों व छात्रों को आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस, डिजिटल टूल्स, साइबर सुरक्षा, वेब व एप डेवलपमेंट, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, डिजिटल कानून तथा स्टार्टअप जैसे विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एके झा ने किया, जबकि इस अवसर पर मुख्य अतिथि जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमर सिंह व विशिष्ट अतिथि आईक्यूएसी के निदेशक सह केयू में भौतिकी के विभागाध्यक्ष डॉ. रंजीत कुमार कर्ण उपस्थित थे।

भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने का मना जश्न

JAMSHEDPUR : नवल टाटा हॉकी अकादमी (एनटीएचए) ने भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम किया, ताकि इस खेल की गौरवशाली विरासत और प्रेरणादायक यात्रा का जश्न मनाया जा सके। इस अवसर पर दो प्रदर्शनी मैच आयोजित किए गए, जो भारत की समृद्ध हॉकी परंपरा और खेल भावना को समर्पित थे। पहले मुकाबले में एनटीएचए ब्लू और एनटीएचए येलो के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पूरे मैच में रोमांच चरम पर था, जहां दोनों टीमों ने शानदार कौशल और बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन किया। अंततः एनटीएचए ब्लू ने कड़े संघर्ष के बाद 3-2 के रोमांचक अंतर से जीत हासिल की। यह मैच दर्शकों के लिए खेल भावना और उत्कृष्ट हॉकी का यादगार प्रदर्शन साबित हुआ। दूसरे मैच में एनटीएचए ग्रासरूट्स-ए और एनटीएचए ग्रासरूट्स-बी के बीच जोशीला मुकाबला हुआ। युवा खिलाड़ियों ने खेल के प्रति जबरदस्त प्रतिभा और जुनून का प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन के दम पर एनटीएचए ग्रासरूट्स-बी ने 5-2 के स्कोर से जीत अपने नाम की। यह आयोजन भारतीय हॉकी की शानदार यात्रा – उसके स्वर्णिम इतिहास से लेकर उज्ज्वल भविष्य की ओर– को समर्पित एक सच्ची श्रद्धांजलि साबित हुआ।

पुलिस ने पशु तस्करी का किया भंडाफोड़, 11 बैल हुए बरामद

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में चक्रधरपुर थाना की पुलिस ने शुक्रवार की सुबह पशु तस्करी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आसनतालिया के पास से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 11 बैलों को बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर बैलों को सोनुवा के चक्रधरपुर रास्ते तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही चक्रधरपुर के थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आसानतालियां के पास नाकेबंदी कर दी। पुलिस की मौजूदगी देखकर तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी 11 बैलों को जब्त कर चक्रधरपुर थाना परिसर में सुरक्षित रखा है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब बैलों के मालिकों और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक तस्कर का नाम सामने आया है, उसकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस की इस कार्रवाई से पशु तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की टीम ने बताया कि पशु तस्करी के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी बैलों को पूर्वी सिंहभूम जिले की चाकुलिया गौशाला भेजा जाएगा।

थाना परिसर में रखे गए बैल

भारतीय जन महासभा ने याद किया साधु-संतों का बलिदान

JAMSHEDPUR : भारतीय जन महासभा ने शुक्रवार को गोवध निषेध के लिए बलिदान हुए साधु-संतों को याद किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म चंद्र पोद्दार ने कहा कि 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा आंदोलन में संसद भवन के पास हजारों साधु-संतों को गोली मार दी गई थी। कई की मौत पुलिस की लाठियों से हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार मनमोहन शर्मा ने 2017 में नई दिल्ली के एक राष्ट्रीय चैनल पर दिए इंटरव्यू में बताया था कि इस आंदोलन में साधु संतों के साथ-साथ आरएसएस, जनसंघ एवं अन्य हिंदू संगठनों की भी सहभागिता रही थी। नरसंहार जैसी संपूर्ण घटना रायसीना हिल्स के चार स्थानों पर घटी थी। इसके पूर्व साधुओं का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिला था। आश्वासन दिया गया था कि गौ रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता बड़ी संख्या में बरामद हुए हथियार

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में उग्रवादी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के खिलाफ सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा की जिला पुलिस व 209 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान के दौरान माओवादियों के ठिकानों से बड़ी संख्या में हथियार के अलावा गोला-बारूद और अन्य सामग्री बरामद की है। बरामद हथियार व सामानों में एसएलएआर (सेल्फ लोडिंग राइफल)-2, 0.303 राइफल-1, 245 कारतूस, 4 मैगजीन, 5 रेडियो सेट, विस्फोटक पदार्थ तथा दैनिक उपयोग की कई सामग्री शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई नक्सल प्रभावित इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। पुलिस के अनुसार, यह बरामदगी माओवादी संगठन की कमजोर होती पकड़ का संकेत है। लगातार चल रहे अभियान से सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन में लगातार सफलता मिल रही है।

बरामद किए गए हथियार ● फोटोन न्यूज

बरामद सामग्री

एसएलआर-2, 0.303 राइफल-1, एके-47 के कारतूस-37, एसएलआर के कारतूस-78, 0.303 के कारतूस-130, 7.62 एमएम मैगजीन-1, एसएलआर मैगजीन-2, 0.303 मैगजीन-1, जिलेटिन पैकेट 6 (प्रत्येक 278 ग्राम, कुल 16.68 किलो), डेटोनेटर सहित तैयार जिलेटिन आईईडी-13, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर-10, नॉन-इलेक्ट्रिक डिटोनेटर-5, रेडियो सेट-5, इंटरसेप्टर-2, सिरिंज-24, आईईडी के लिए प्लास्टिक पाइप (6इ)-20, लैपटॉप (आसुस)-1, लैपटॉप (लेनेवो)-1, एफएम रेडियो-11 एवं अन्य दैनिक उपयोग के सामान।

क्रिटिकल मेटल के निष्कर्षण, सप्लाईचेन व अंतरराष्ट्रीय नीति पर हुआ गहन मंथन

PHOTON NEWS JSR : सीएसआईआर-नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्रिटमेट-2025 में शुक्रवार को क्रिटिकल मेटल के निष्कर्षण, वितरण और लाभ के साथ-साथ सप्लाईचेन और अंतरराष्ट्रीय नीति पर भी गहन चर्चा हुई। मुख्य वक्तव्य (की-नोट लेक्चर) स्वीडन के केटीएच संस्थान की प्रो. कुर्स्टिन फोर्सबर्ग ने दिया, जो क्रिस्टलाइजेशन और प्रीसिपिटेशन तकनीकों की विशेषज्ञ हैं। उन्होंने क्रिटिकल रॉ मैटेरियल प्रोसेसिंग में इन तकनीकों द्वारा उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। वहीं, प्लेनरी लेक्चर एमआईटी, यूएसए के प्रो. अमिल्टन बारबोसा बोटेल्हो जूनियर ने क्रिटिकल मेटल के पृथक्करण के लिए सपोर्टेड लिक्विड मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रोडायलिसिस के संयोजन विषय पर प्रस्तुत किया। सत्रों में जीएमडीसी, टीसीएस, टाटा स्टील और एसएंडपी ग्लोबल जैसे उद्योग-संगठनों के विशेषज्ञों ने भी अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन में शोध संस्थानों, उद्योगों और नीति-निर्माण से जुड़े 275 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जो क्रिटिकल मेटल के क्षेत्र को समृद्ध बना रहे हैं। कार्यक्रम में क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके साथ ही नवीनतम अनुसंधान को प्रदर्शित करने वाले पोस्टर सत्र का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. कुर्स्टिन फोर्सबर्ग को स्मृतिचिह्न देते डॉ. बीडी पांडेय

रोटरी वेस्ट ने स्कूली छात्रों के बीच कराई विभिन्न प्रतियोगिताएं

JAMSHEDPUR : रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट ने इंटरैक्ट क्लबों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। 3 से 7 नवंबर तक हुए वर्ल्ड इंटरैक्ट वीक के कार्यक्रम में मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, चर्च स्कूल बेलडीह, काशीडीह हाई स्कूल, केरल समाजम मॉडल स्कूल और डीबीएमएस करियर एकेडमी के छात्र शामिल हुए। छात्रों ने अंतर-विद्यालय रचनात्मक लेखन, वाद-विवाद, लोकगीत, लोकनृत्य व ड्रॉइंग प्रतियोगिता हुई। शुक्रवार को हुए समापन समारोह में अध्यक्ष अशोक झा, डॉ. जूही समर्पिता, अंजनी निधि, विनीता झा आदि भी उपस्थित थीं।

बाईपास सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने की सभा

बैठक करते ग्रामीण ● फोटोन न्यूज

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में जगन्नाथपुर प्रखंड के बड़ानन्दा स्थित पीपल पेड़ के पास शुक्रवार को रैयत संघर्ष समन्वय समिति व झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संयुक्त तत्वावधान में बैठक हुई, जिसमें बड़ानन्दा, कंसलापोस, जगन्नाथपुर, जिन्तुगाढ़ा व पोदनासाई बाईपास सड़क पर चर्चा की गई। इसमें पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा ने कहा कि बिना ग्रामसभा की सहमति के जबरन भूमि अधिग्रहण करना षडयंत्र है। रैयतों को एकजुट होकर लड़ने का अब समय आ गया है। महासचिव अमृत माझी ने कानूनी लड़ाई पर जोर दिया। इस सभा को छात्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अरिल सिंकु, मुखिया हीरामनी केराई, जिला अध्यक्ष नारायण सिंह पुरती, आशा पुरती, खूंटकटी रैयत रक्षा समिति चाईबासा के अध्यक्ष बलभद्र सवैयां, केदार कालुंडिया, कृष्णा बोबोंगा, गंगाराम सिंकु, बासिल हेम्ब्रम, आदिवासी एसोसिएशन नोवामुंडी के अध्यक्ष घनश्याम हेम्ब्रम, सालुका बोबोंगा, योगेंद्र सिंकु आदि ने भी संबोधित किया।

शिक्षा कोल्हान विश्वविद्यालय में को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज में 18 महीने पीछे चल रही नामांकन की प्रक्रिया

एलएलबी एंट्रेंस के नतीजे जारी, 22 को आएगी पहली मेधा सूची

PHOTON NEWS JSR : कोल्हान विश्वविद्यालय (केयू) ने आखिरकार एलएलबी प्रवेश परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा 14 सितंबर को हुई थी, जिसमें कुल 320 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परिणाम आने में करीब डेढ़ माह की देरी हुई, जिसके कारण सत्र 2024-27 के लिए दाखिला प्रक्रिया में और विलंब हुआ है। अब पहली मेधा सूची 22 नवंबर को जारी की जाएगी और इसके आधार पर 1 दिसंबर तक जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज में संचालित तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स में दाखिला लिया जा सकेगा। इसके बाद सीट खाली रहने पर दूसरी मेधा सूची जारी की जाएगी। कॉलेज में एलएलबी की कुल 120 सीटें निर्धारित हैं। दाखिला पूरी तरह मेधा सूची के आधार पर होगा।

एडमिशन की प्रमुख तिथि

प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन	:	22 नवंबर
प्रथम मेधा सूची के आधार पर दाखिला	:	22 नवंबर से 1 दिसंबर
दूसरे मेधा सूची का प्रकाशन	:	4 दिसंबर
दूसरे मेधा सूची के आधार पर दाखिला	:	4 से 11 दिसंबर
तीसरे मेधा सूची का प्रकाशन	:	13 दिसंबर
तीसरे मेधा सूची के आधार पर दाखिला	:	13 से 19 दिसंबर

डेढ़ साल की देरी से हो रहा दाखिला : यह दाखिला सत्र 2024-27 के लिए है, लेकिन देरी के कारण यह प्रक्रिया करीब 18 महीने पीछे चल रही है। सामान्यतः जुलाई-अगस्त में शुरू होने वाला सत्र अब जनवरी 2026 से शुरू होगा, जिससे छात्रों का डेढ़ साल पहले ही व्यर्थ हो चुका है। कई अभ्यर्थियों ने इस देरी पर रोष जताया है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और मेधा सूची भी इसी पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियों को दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक कॉलेज पहुंचना होगा। परीक्षा के बाद परिणाम और दाखिले में इतना विलंब होने से उनकी पढ़ाई और करियर पर गहरा असर पड़ा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने देरी के लिए तकनीकी और प्रशासनिक कारणों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन छात्रों का मानना है कि बेहतर प्रबंधन से इस स्थिति से बचा जा सकता था। अब छात्रों की निगाहें मेधा सूची पर टिकी हैं, ताकि वे समय रहते दाखिला पूरा कर सकें। यह देरी कोल्हान विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया में बार-बार सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करती है। छात्रों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी देरी न हो और समयबद्ध तरीके से परीक्षा, परिणाम और दाखिला प्रक्रिया पूरी की जाए।

फिडे रेटिंग चेस में देशभर के 345 खिलाड़ी ले रहे भाग

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में आयोजित रुंगटा सीमेंट ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटिंग चेस कंपटीशन में देशभर के 345 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन शुक्रवार को दो राउंड का खेल खेला गया। पांचवें राउंड में इंटरनेशनल मास्टर आर्यन वार्ष्णेय ने बंगाल के अबीर मित्र को, इंटरनेशनल मास्टर शुभयान कुंडू ने झारखंड के कृष्ण कुमार साहू को, फिडे मास्टर कुमार गौरव ने ओडिशा के शिवम सत्यांश को परास्त किया। बंगाल के डिप्रो मंडल एवं बिहार के कृष्ण कुमार के बीच मुकाबला बराबरी पड़ रहा। छठे राउंड में दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय मास्टर आर्यन वार्ष्णेय ने बंगाल के इंटरनेशनल मास्टर शुभयान कुंडू, ओडिशा के श्रेयांश शुभम पटनायक एवं बिहार के कुमार गौरव के बीच बराबरी पर मुकाबला रहा। वहीं, बंगाल के रूप मुखर्जी ने झारखंड के विभाष कुमार को, बंगाल के अनुराग जायसवाल ने झारखंड के कमल किशोर देवनाथ को परास्त किया।

ग्रीष्मकालीन भिंडी उत्पादन की उन्नत तकनीक

ग्रीष्मकालीन सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है। ग्रीष्मकाल में भिंडी की अगेती फसल लगाकर किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते है। मुख्य रुप से भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खनिज लवणों के अतिरिक्त विटामिन 'ए', 'सी' थाईमीन एवं रिबोफ्लेविन भी पाया जाता है। भिंडी के फल में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। भिंडी का फल कब्ज रोगी के लिए विशेष गुणकारी होता है। इस लेख में ग्रीष्मकालीन भिंडी की उत्पादन तकनीक की विवेचना की गयी है:-

जलवायु एवं भूमि की तैयारीः- भिंडी के उत्पादन हेतु गर्म मौसम अनुकुल होता है। बीजों के अंकुरण हेतु 20 सेंटीग्रेड से कम का तापमान प्रतिकूल होता है। 42 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर फूल का परागण नहीं होता है एवं फूल गिर जाते है।

सामान्यतः भिंडी की खेती सभी प्रकार की भूमियों पर की जा सकती है परन्तु हल्की दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश उपलब्ध हो एवं उचित जल निकास की सुविधा हो, भिंडी की खेती हेतु श्रेष्ठ होती हैं। भूमि की दो-तीन बार जुताई कर भूरभूरा कर तथा पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए।

उन्नत किस्में- अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभणी क्रांति, पूसा-ए-4, वर्षा उपहार,

बीज एवं बीजोपचारः- ग्रीष्मकालीन फसल हेतु 18-20 कि.ग्रा. बीज एक हेक्टर बुवाई के लिए पर्याप्त होता है जबकि वर्षाकालीन फसल में अधिक बढ़वार की कारण 12-15 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टर उपयोग करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन भिंडी के बीजों को बुवाई के पूर्व 12-24 घंटे तक पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुवाई के पूर्व भिंडी के बीजों को 3 ग्राम थायरम या कार्बेन्डाजिम प्रति किलो बीजदर से उपचारित करना चाहिए। संकर किस्मों के लिए 5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर की बीजदर पर्याप्त होती है।

बुवाईः- ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई फरवरी-मार्च में की जाती है। फिर भी अगेती फसल हेतु छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 15 जनवरी के बाद भी बुवाई की जा सकती हे। यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी है तो तीन सप्ताह के अंतराल पर फरवरी से जुलाई के मध्य अलग-अलग खेतों में भिंडी की बुवाई की जा सकती है।

ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार दूरी 25-30 सें.मी. एवं कतार में पौधे की मध्य दूरी 15-20 से.मी. रखनी चाहिए। वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार दूरी 40-45 सें.मी. एवं कतारों में पौधे की बीच 25-30 सें.मी. का अंतर रखना उचित रहता है।

पोषण प्रबंधनः- भिंडी की बुवाई के दो सप्ताह पूर्व 250-300 क्विंटल सड़ा हुआ गोबर खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। प्रमुख तत्वों में नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश क्रमशः 60 कि.ग्रा., 30 कि.ग्रा. एवं 50 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर की दर से मिट्टी में देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व भूमि में देना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को दो भागों में 30-40 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए।

जलप्रबंधनः- यदि भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो बुवाई के पूर्व एक सिंचाई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में प्रत्येक पांच से सात दिन के अंतराल पर सिंचाई आवश्यक होती है। बरसात में आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए तथा अतिवृष्टि के समय उचित जलनिकास प्रबंध करना चाहिए।

निदाई-गुड़ाईः- नियमित निंदाई-गुड़ाई कर खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। बोने के 15-20 दिन बाद प्रथम निंदाई-गुड़ाई करना जरुरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण हेतु रासायनिक नींदानाशकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बासालिन को 1.2 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टर की दर से पर्याप्त नम खेत में बीज बोने के पूर्व मिलाने से प्रभावी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है।

फल की तोड़ाई एवं उपजः- किस्म की गुणता के अनुसार 45-60 दिनों में फलों की तुड़ाई प्रारंभ की जाती है एवं 4 से 5 दिनों के अंतराल पर नियमित तुड़ाई की जानी चाहिए। ग्रीष्मकालीन भिंडी फसल में उत्पादन 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टर तक होता है।

पौध संरक्षणः- भिंडी के प्रमुख रोग पीत शिरा मौजक एवं चूर्णिल आसिता एवं नुकसानदायक कीट प्ररोह एवं फल छेदक तथा जैसिड है।

पीत शिरा रोगः- यह भिंडी की फसल में नुकसान पहुचाने वाला प्रमुख रोग है। इस रोग के प्रकोप से सर्वप्रथम पत्तियों की शिराएं पीली पड़ने लगती है। तत्पश्चात पूरी पत्तियाँ एवं फल भी पीले रंग के हो जाते है पौधे की बढ़वार रुक जाती है। वर्षा ऋतु में इस रोग का संक्रमण अधिक होता है।

सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण वाले पौधे दिखाई देते ही उन्हें उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। यह विषाणु जनित रोग सफेद मक्खी कीट द्वारा स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। अतः रोग संवाहक कीट के नियंत्रण हेतु आक्सी मिथाइल डेमेटान 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से रोग का प्रसारण कम होता है। पीतशिरा रोग प्रतिरोधी किस्मों जैसे अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभणी क्रांति इत्यादि का चुनाव करना चाहिए। फसल के चारों ओर 2-3 कतार मक्का बोने से भी रोग का फैलाव नियंत्रित किया जा सकता है।

चूर्णिल आसिताः- इस रोग में भिंडी की पुरानी निचली पत्तियों पर सफेद चूर्ण युक्त हल्के पीले धब्बे पड़ने लगते है। ये सफेद चूर्ण वाले धब्बे काफी तेजी से फैलते है। इस रोग का नियंत्रण न करने पर पैदावार 30 प्रतिशत तक कम हो सकती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 या 3 बार 12-15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए।

प्ररोह एवं फल छेदकः- इस कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में इल्ली कोमल तने में छेद करती है जिससे तना सूख जाता है। फूलों पर इसके आक्रमण से फल लगने के पूर्व फूल गिर जाते है। फल लगने पर इल्ली छेदकर उनको खाती है जिससे फल मुड़ जाते हैं एवं खाने योग्य नहीं रहते है।

जैसिडः- ये सुक्ष्म आकार के कीट पत्तियों, कोमल तने एवं फल से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते है।

फल छेदक के द्वारा आक्रमण किये गये फलों एवं तने को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। क्विनॉलफास 25 ई.सी. 1.5 मिली लीटर या इंडोसल्फान 1.5 मिली लीटर प्रति लीटर पानी की दर से कीट प्रकोप की मात्रा के अनुसार 2-3 बार छिड़काव करने से जैसिड एवं फल प्ररोह छेदक कीटों का प्रभावी नियंत्रण होता है। फल बनने के उपरांत कीट प्रकोप होने पर 'फेनवेलरेट' 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर उपर्युक्त बनाये कीटनाशक के साथ अदल-बदल कर प्रयोग करें।

कैसे करें संरक्षित खेती

संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य सब्जी फसलों को मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है।

संरक्षित सब्जी उत्पादन के लिए सब्जी उत्पादकों को संरक्षित खेती व विभिन्न संरक्षित संरचनाओं की पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही उत्पादक तय कर सकता है कि वह किस प्रकार की संरक्षित तकनीक अपनाकर बेमौसमी सबजियों का उत्पादन करे। कौन कौन सी संरक्षित प्रौद्योगिकीयाँ हैं जिनमे वह सबजियों को वर्ष भर उगा सकता है। संरक्षित संरचनाओं को बनाने के बाद में रख रखाव में क्या व्यय होगा तथा उच्च गुणवत्ता वाली सबजियों को वह किस बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सकता है। इन सभी विषयों की जानकारी आवश्यक है।

मुख्यतः सब्जी उत्पादन हेतू उचित व उपयुक्त संरक्षित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती है। लेकिन इसके अलावा किसान की आर्थिक दशा, टिकाऊ व उच्च बाजारकी उपलब्धता व बिजली की उपलब्धता आदि कारक भी इसको निर्धारित करते है। सब्जीयों के बेमौसमी उत्पादन हेतू मुख्यत : वातावरण अनुकूलित ग्रीनहाउस, प्राकृतिक वायु संचारित ग्रीनहाउस, कम लागत वाले पॉलीहाउस, वाक-इन-टनल, कीट अवरोधी नेटहाउस तथा लो प्लास्टिक टनल आदि संरचनाओं का उपयोग किया जाता है।

बेमौसमी सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए सबजियों की पौध प्लग ट्रे पद्धती से ग्रीनहाउस मे तैयार की जाती है। तथा उसके बाद पौधो को उपयुक्त संरक्षित संरचना में रोपाई करते है।

वाक-इन- टनल तकनीक

वाक-इन- टनल एक प्रकार की अस्थाई संरक्षित संरचना है जो आधा इंच मोटाई के जंग रोधी पाईपों को अर्धगोलाकार आकार मे मोडकर तथा इन्हे सरियों के टुकडो के सहारे खेत में खडा करके उसके ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक की चादर से ढककर बनाया जाता है। इसके मध्य में ऊंचाई लगभग 6 से 6.5 फुट तथा जमीन पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चौडाई 4 मीटर तक होती है।

इस प्रकार की संरक्षित संरचनाओं को सर्दी के मौसम में बेमोसमी सब्जी जैसे लोकी, खरबूजा, तरबूज, खीरा, चप्पनकद्दू , तथा अन्य कद्दू वर्गीय सब्जीयां उगाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की संरक्षित संरचनाओं में दिन के समय जब सूर्य की रोशनी प्लास्टिक पर मडती है तो टनल के अन्दर का तापमान काफी (लगभग 10 से 12 डि.ग्री से.) बढ जाता है । जिससे कद्दू वर्गीय सब्जीयों को कम तापमान के दिनो में भी बढवार करने में सफलता मिल जाती है।

वाक-इन- टनल की लम्बाई आवश्यकता अनुसार बढाई जा सकती है। लेकिन सामान्यत- इनकी लम्बाई 25 से 30 मीटर होती है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं- प्लास्टिक की चादर की उपलब्ध माप, टनल में हवा का आदान प्रदान, तथा इस लम्बाई के टनल में मधुमक्खीयों को भी परागण कार्य करने में कोई असुविधा नही होती। इन संरचनाओं को बनाने में लागत भी बहुत कम ही आती है। तथा अस्थाई होने के कारण इनकी देखभाल भी सरलता पूर्वक की जा सकती है।

इन संरचनाओं का उपयोग केवल सर्दी के मौसम (दिसम्बर जनवरी व फरवरी माह) में ही फसल उत्पादन के लिए किया जा सकता है। क्योकि सर्दी के बाद इसके अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ जाता है तथा हवा का अधिक आदान प्रदान न होने के कारण तब इनमे फसल उगाना संभव नही होता है। यही नही इनका उपयोग पहाडी क्षेत्रों मे और भी लम्बे समय तक सब्जी उत्पादन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार इन संरचनाओं को ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों मे भी सब्जी उत्पादन के लिए उपयोग मे लाना सम्भव है।

छतरपुर के गांधी आश्रम में जैविक खेती का अद्भुत प्रयोग

यहां जैविक, परंपरागत और टिकाऊ खेती की किताबी बातें नहीं की जातीं बल्कि जमीन पर नजर भी आती हैं। कड़कड़ाती ठंड और पाला भी इस इलाके में लगी दलहनी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पेड़-पौधों की रंगत देखकर ही लगता है कि यहां की मिट्टी ने अपनी खोयी ताकत और ऊर्जा फिर पा ली है। यह कोई वर्षों की मेहनत नहीं बल्कि केवल चार साल की लगन का नतीजा है। मिसाल पेश करने वाले हैं - संजय और दमयंती। जिस बुंदेलखंड में पिछले पांच सालों में भयंकर सूखे से किसानों की कमर टूट गई है, उसी धरती पर एक जगह ऐसी भी है, जहां खुशियों की खेती लहलहा रही है। विदर्भ के बाद मध्यप्रदेश में किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के बीच खेती का यह प्रयोग एक मिसाल पेश करता है। यहां जैविक, परंपरागत और टिकाऊ खेती की किताबी बातें नहीं की जातीं बल्कि जमीन पर नजर भी आती हैं। कड़कड़ाती ठंड और पाला भी इस इलाके में लगी दलहनी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पेड़-पौधों की रंगत देखकर ही लगता है कि यहां की मिट्टी ने अपनी खोयी ताकत और ऊर्जा फिर पा ली है। यह कोई वर्षों की मेहनत नहीं बल्कि केवल चार साल की लगन का नतीजा है। मिसाल पेश करने वाले है संजय और दमयंती और जगह है छतरपुर।

टिकाऊ खेती की बात से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी होगा। गांधी आश्रम छतरपुर ऐतिहासिक महत्व की जगह है। अंग्रेजी शासन काल के बाद दीवान साहब के बंगले से यह जगह गांधी विचारों को आगे ले जाने का एक केन्द्र बनी। तत्कालीन दीवान ने विनोबा के भूदान आंदोलन से प्रेरित होकर इस बंगले और बंगले से लगी जमीन को गांधी विचारों के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद इसे गांधी आश्रम के नाम से विकसित किया गया। सांस्कृतिक-साहित्यिक-सामाजिक गतिविधियों को यहां से संचालित किया जाता रहा। सत्तर के दशक में जब चंबल में डाकुओं का आतंक अपने चरम पर पहुंचकर आत्मसमर्पण की ओर बढ़ा तब इस प्रक्रिया की बुनियाद इसी आश्रम के पुस्तकालय से पड़ी। जयप्रकाश नारायण के साथ यहां डाकुओं की बातचीत हुई और इसके बाद डाकुओं ने आत्मसमर्पण भी किए। गांधी का ग्रामस्वराज, बुनियादी तालीम और टिकाऊ विकास की अवधारणाओं की झलक इस छोटे से आश्रम में दिखाई देती है। बीच में एक लंबा दौर ऐसा भी आया जब यह आश्रम भूमाफियों और सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र में तब्दील हो गया।

2006 में गांधी विचारों से जुड़े संजय और दमयंती जब इस जगह आए तो उन्होंने ठान लिया कि यहां की तस्वीर को बदलने के लिए वह कठिन परिश्रम करेंगे। खेती-किसानी और प्रकृति प्रेमी भाई ने इस आश्रम से लगे लगभग चालीस एकड़ खेत में जैविक खेती के प्रयोग को शुरू करने की योजना बनाई। एक ओर जहां नकद फसलों ने फसलों की विविधता को खत्म कर दिया है वहीं इस आश्रम में उन्होंने अलग-अलग फसलों को अपनाया। इस छोटी सी जमीन पर गेहूं, चना, सरसों, अरहर, ज्वार, मक्का, जौं सहित ऐसी फसलें लीं जो सीधे-सीधे किसान अपने खाने के लिए भी उपयोग करते हैं। दरअसल खेती का परंपरागत तरीका था भी यहीं कि किसान ज्यादातर खाद्यान्न और मसाले अपने खेतों में पैदा किया करते थे और उन्हें हर चीज के लिए बाजार की ओर मुंह नहीं देखना पड़ता था, अब किसान गेहूं-सोयाबीन पैदा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन दाल-मसालों के लिए वह बाजार पर निर्भर है। खेती की इस विविधता से आश्रम की व्यवस्थाएं भी स्वतः संचालित होती है। यहां तक की सब्जी और फलों का उत्पादन भी आश्रम से ही हो जाता है। इस खेती की सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चार सालों से यहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। वर्मी कम्पोस्ट और गोमूत्र के जरिए यहां की फसलों को जान मिलती है। 40 एकड़ के इस क्षेत्र को आश्रम के केवल सात कार्यकर्ता अंजाम देते हैं। संजय भाई बताते हैं कि आज के इस दौर में जैविक खेती करना थोड़ा कठिन जरूर लग सकता है पर यह असंभव कतई नहीं है। हम अपने खेतों में उतना ही समय खर्च करते हैं जितना दूसरे किसान। पर यहां आपको यह समझना होगा कि जमीन क्या चाहती है। किस तरह की जमीन पर किस तरह के फसल ठीक रहेगी यह समझना होगा।इस आश्रम की एक खास बात यह है कि आप यहां पूरी तरह जैविक भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहां तक की दाल-मसाले और तेल भी खुद की उगाई गई तिल का। इस आश्रम में चल रही खेती के प्रयोग को समझने फ्रांस के निकोलस आए हैं। निकोलस कहते हैं कि 'वह भारत में जैविक खेती के अलग-अलग प्रयोगों को उन्होंने देखा, लेकिन यह प्रयोग सबसे अद्भुत है। इसलिए भी क्योंकि यह गांधी के विचारों से जुड़ा हुआ है। गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे और गांव की अर्थव्यवस्था के एक मॉडल की बात करते थे जहां कि ग्रामवासी आपसी व्यवहार में अपने साझा जीवन को अंजाम देते थे। यह प्रयोग अपने आप में दिलचस्प है।' यही कारण है कि वह न केवल इस खेती पर अध्ययन कर रहे हैं बल्कि इस प्रयोग के साथ इतना रम गए हैं कि वह खुद खेतों में पसीना बहाते हैं। बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता भावेश भी इस प्रयोग के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। वह कहते हैं कि कम लागत की इस खेती को जीवन के साथ जोड़कर भी देखा जाना जरूरी है।

नौकरशाही के दरबार में फाइलों के बीच दम तोड़तीं संवेदनाएं

हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि समाज अन्याय से भर गया है, बल्कि यह है कि संवेदनाएं खोती जा रही हैं। जिस देश में सरकारी तंत्र सेवा का प्रतीक होना चाहिए था, वहां अब नौकरशाही शब्द ही अहंकार और दूरदर्शिता की कमी का पर्याय बन चुका है। सरकारी तंत्र जब संवेदनहीन हो तो व्यवस्था का चेहरा निर्दयी हो जाता है। छोटी सी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति फाइलों के जंगल में भटकता है। फोन उठाने से लेकर जवाब देने तक हर कदम पर दीवार खड़ी है- उस दीवार का नाम है नौकरशाही की असंवेदनशीलता। नौकरशाही का मूल उद्देश्य नागरिकों की सुविधा, प्रशासन की पारदर्शिता और नीतियों की समानता था। लेकिन, धीरे-धीरे यह वर्ग अपने ही बनाए दायरे में कैद हो गया। सत्ता के निकट रहकर उसने सेवा को सत्ता-साझेदारी में बदल दिया। आज अधिकारी जनता के प्रतिनिधि नहीं, सत्ता के प्रतिनिधि बन चुके हैं। फाइलों पर फैसले अब संवेदना से नहीं,किसे खुश करना है और किससे बचना है जैसी मानसिकता से लिए जाते हैं। इस मानसिकता ने शासन को जीवंतता से दूर कर दिया है। नौकरशाही अब अपने भीतर ऐसा प्रशासनिक अहंकार पाल चुकी है, जो हर आलोचना को शत्रुता समझता है। फाइलें महीनों दबाई जाती हैं, नियुक्तियां वर्षों तक लंबित रहती हैं और जब जवाब मांगा जाए तो कहा जाता है- प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया अब बहाने का दूसरा नाम बन चुकी है। जनता के सवालों का जवाब कागजों में मिलता है, लेकिन न्याय का उत्तर शून्य में खो जाता है। सत्ता अपने स्वभाव में आकर्षक होती है। यह व्यक्ति को शक्ति देती है, पर उसी शक्ति के साथ चरित्र की परीक्षा भी लेती है। दुर्भाग्य से, हमारे समय की राजनीति ने इस शक्ति को ज्यादातर जिम्मेदारी नहीं, बल्कि विशेषाधिकार समझ लिया है। सत्ताधारी तब तक सक्रिय रहते हैं, जब तक प्रशंसा मिलती रहती है। लेकिन, आलोचना या असहमति के क्षणों में उनकी सहनशीलता समाप्त हो जाती है। यही संवेदनहीन सत्ता का भयावह रूप है- जहां जनता की पीड़ा आंकड़ों में बदल दी जाती है और आंकड़ों की भाषा में संवेदना मर जाती है। हर बार जब कोई त्रासदी होती है- दुर्घटना, दंगा या भ्रष्टाचार- तब जमीनी स्तर पर प्रशासन केवल रिपोर्ट तैयार करता है, जिनमें संवेदना नहीं, केवल डेटा होता है। यह स्थिति लोकतंत्र की उस आत्मा को चोट पहुंचाती है, जो जन से शुरू होकर जन पर ही समाप्त होती है। संवेदनहीनता केवल प्रशासन की नहीं समाज की भी बीमारी बन चुकी है। आज दुर्घटनाओं के वीडियो बनाए जाते हैं, पर किसी की मदद करने की हिम्मत कम ही होती है। गरीब की पीड़ा पर ताली बजाना आसान है, पर मदद करना कठिन। यह वही मानसिकता है, जिसने एक गहरी खाई बना दी है। जहां ऊपर बैठे लोग नीतियों की बात करते हैं, वहीं नीचे खड़े लोग रोटी की। नौकरशाही- जो पुल नहीं, दीवार बन चुकी है। यही वह त्रासदी है, जो लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर रही है। एक समय था जब सरकारी अधिकारी जनसेवक कहलाते थे। यह शब्द अब मजाक लगता है। आज का प्रशासन इतना प्रक्रियात्मक हो गया है कि वह मनुष्यता को भूल गया है। फाइलों और कानूनों की दुनिया में संवेदना को अपवाद मान लिया गया है। यह विचलित करने वाली सच्चाई है कि जो तंत्र जनता की सेवा के लिए बना, वही तंत्र अब नागरिक को संदेह की दृष्टि से देखता है। अधिकारी जनता को सुविधा देने से अधिक उसके इंटेंशन पर शक करने लगे हैं। यह शक लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है। नौकरशाही और सत्ता के बीच यह मानसिक दूरी अब सामाजिक असमानता को और गहरा रही है। गांवों में सड़क तब पहुंचती है, जब वोट की जरूरत पड़ती है। स्कूलों में शिक्षक तब लगते हैं जब मीडिया हंगामा करती है। अस्पतालों में दवा तब आती है जब मंत्री का दौरा तय होता है। यह संवेदनहीन तंत्र आम नागरिक की जिंदगी को उस प्रतीक्षा की यातना में बदल देता है, जो कभी समाप्त नहीं होती। संवेदनहीनता की यह संस्कृति सरकारी तंत्र की स्थायी साथी बन चुकी है। हम यह भूल चुके हैं कि शासन का सार मनुष्यता में निहित है। कानून तभी तक उपयोगी हैं, जब वे मानवीयता की रक्षा करें और प्रशासन तभी तक वैध है, जब वह नागरिक के दुख को अपनी जिम्मेदारी माने। आज हमारे देश में हर विभाग में योजनाएं हैं, लेकिन क्रियान्वयन में संवेदना नहीं है। यही कारण है कि योजनाएं रिपोर्ट कार्ड बनकर रह गई हैं, न कि राहत का साधन। जरूरत इस बात की है कि सरकारी तंत्र को फिर से सेवा का पर्याय बनाया जाए। शासन में इमोशनल इंटेलिजेंस को नीतिगत अनिवार्यता बनाया जाए। नौकरशाही को प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रोटोकॉल नहीं, संवेदना भी सिखाई जाए। पद का अहंकार अगर सेवा की भावना से नहीं मिला, तो हर नीति अधूरी रह जाएगी। आज आवश्यकता अकुशल प्रशासनिक मशीनरी की नहीं, मानवीय प्रशासन की है- जहां प्रत्येक निर्णय के केंद्र में नागरिक का दुख, उसकी गरिमा और उसका जीवन हो। हमारे समय का असली सुधार यही होगा कि नौकरशाही और सत्ता में संवेदना वापस लाई जाए। कानून की कठोरता के साथ मानवीयता की कोमलता भी जरूरी है। आज अगर हम सरकारी तंत्र में फिर से मनुष्यता को जीवित नहीं कर पाए, तो अगली पीढ़ियां हमें संवेदनहीन युग कहकर याद करेंगी। शायद तब यह प्रश्न उठेगा कि क्या हमने शासन को इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया।

मनगढ़ंत कहानियों के जरिए संघ पर हमले के निहितार्थ

ANALYSIS

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

नतीजतन, किसी भी खामोश व्यक्ति या समूह पर कीचड़ उछालना आसान है। मिशनरियों, इस्लामी चरमपंथियों और कुछ राजनीतिक दलों ने आरएसएस को बदनाम करना शुरू कर दिया और इस संगठन को असंवैधानिक रूप से गैरकानूनी घोषित करने की बात करने लगे। समकालीन भारतीय राजनीति के प्रामाणिक अध्ययनों के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार वाल्टर के. एंडरसन ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस को पश्चिम और भारत में भी कई लोगों की तरह एक धार्मिक संगठन समझने की भूल कर बैठे हैं। यह रणनीति राहुल गांधी के खुद को हिंदू और देशभक्त के रूप में पेश करने के प्रयासों को कमजोर कर सकती है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में दक्षिण एशिया अध्ययन के पूर्व प्रमुख एंडरसन लगभग 50 वर्षों तक आरएसएस का गहन अध्ययन करने के लिए जाने जाते हैं। वे ब्रदरहुड इन सैफ्रन जैसी पुस्तकों के लेखक हैं। उन्होंने चर्चा की कि पश्चिम में आरएसएस को कैसे देखा जाता है, उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है- जैसे जातिगत भेदभाव का समाधान-अल्पसंख्यकों तक कैसे पहुंचा जाए और बौद्धिक अभिजात वर्ग का दिल कैसे जीता जाए और भाजपा के भविष्य के बारे में उनका दृष्टिकोण।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के दौरान संघ की गतिविधियों के खिलाफ घिनौने झूठे आख्यान और राजनीति से प्रेरित प्रयास हमारे महान राष्ट्र के विरोधियों के बीच अभूतपूर्व भय का प्रदर्शन करते हैं। आरएसएस एक मूक संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जो समाज में विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने में विश्वास करता है। हम सभी जानते हैं, शब्दों का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं हो सकता, लेकिन किसी के प्रयासों का प्रभाव हो सकता है। इसी धारणा के आधार पर आरएसएस भारतीयों और राष्ट्र की मदद, विकास और एकता के अपने प्रयासों का कभी प्रचार नहीं करता। नतीजतन, किसी भी खामोश व्यक्ति या समूह पर कीचड़ उछालना आसान है। मिशनरियों, इस्लामी चरमपंथियों और कुछ राजनीतिक दलों ने आरएसएस को बदनाम करना शुरू कर दिया और इस संगठन को असंवैधानिक रूप से गैरकानूनी घोषित करने की बात करने लगे। समकालीन भारतीय राजनीति के प्रामाणिक अध्ययनों के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार वाल्टर के. एंडरसन ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस को पश्चिम और भारत में भी कई लोगों की तरह एक धार्मिक संगठन समझने की भूल कर बैठे हैं। यह रणनीति राहुल गांधी के खुद को हिंदू और देशभक्त के रूप में पेश करने के प्रयासों को कमजोर कर सकती है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में दक्षिण एशिया अध्ययन के पूर्व प्रमुख एंडरसन लगभग 50 वर्षों तक आरएसएस का गहन अध्ययन करने के लिए जाने जाते हैं। वे ब्रदरहुड इन सैफ्रन जैसी

पुस्तकों के लेखक हैं। उन्होंने चर्चा की कि पश्चिम में आरएसएस को कैसे देखा जाता है, उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है- जैसे जातिगत भेदभाव का समाधान-अल्पसंख्यकों तक कैसे पहुंचा जाए और बौद्धिक अभिजात वर्ग का दिल कैसे जीता जाए और भाजपा के भविष्य के बारे में उनका दृष्टिकोण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कुछ अन्य नेताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति उनके खराब नजरिए के लिए जाना जाता है। इस धारणा और राहुल गांधी द्वारा उस पर किए गए मुखर हमलों के बावजूद आरएसएस उनसे घृणा नहीं करता। इसका कारण संघ का दर्शन, नेतृत्व का इतिहास और उनकी विचार प्रक्रिया है, जो एक सदी में विकसित हुई है। स्वतंत्रता के बाद से ही आरएसएस ने राष्ट्र प्रथम की मानसिकता को बनाए रखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ सहयोग किया है। आरएसएस पर हमला करने की कोशिश में वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व विडंबनापूर्ण रूप से अपने ही अतीत की उपेक्षा कर रहा है, जिसमें कई कांग्रेस नेताओं ने कई विषयों पर आरएसएस के साथ घनिष्ठ सहयोग किया है। संघ का सौ साल का इतिहास इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करता है कि हजारों स्वयंसेवकों ने राष्ट्र की सेवा में जीवन त्याग दिया या अपनी जान गंवाई और इस दौरान एकता, राष्ट्रीय पहचान और हिंदू जागरण के सिद्धांतों पर अडिग रहे। राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचना और कार्य करना आरएसएस का एकमात्र दायित्व है। हजारों लोग प्रचारक के रूप में काम करते हैं, जो राष्ट्र की सेवा के एकमात्र उद्देश्य के साथ एक त्यागी जीवन जीते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान या जब भी राष्ट्र को आवश्यकता हो, आरएसएस सभी जाति-धर्म के लोगों की मदद और समर्थन के लिए तैयार रहता है। कुछ उदाहरण हैं- चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित अवैध आपातकाल के खिलाफ लड़ाई, पंजाब में अशांति के दौरान शांति प्रक्रिया और समाज को दोबारा एकजुट करने के लिए किए गए प्रयास। जो लोग भारत की विरासत, कला और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें हमेशा आरएसएस के विरोध का सामना करना पड़ेगा। चूंकि भारत में बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं, इसलिए आरएसएस हिंदू समुदाय या भारतीयता को विभाजित या विघटित करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगा, चाहे विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। नफरत करने वाले आरएसएस को बदनाम करने और सभी भारतीयों को भयभीत करने की अपनी लंबे समय से चली आ रही रणनीति को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह रणनीति यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक भाजपा के खिलाफ एकजुट रहें और भाजपा के मतदाताओं के दिलों में भी डर पैदा हो, क्योंकि अधिकतर भाजपा पदाधिकारियों की पृष्ठभूमि आरएसएस से है। स्वार्थी प्रेरणा या लालची प्रवृत्ति वाले किसी भी व्यक्ति के लिए समाज और राष्ट्र कभी भी सर्वोच्च उद्देश्य नहीं होते। वे राष्ट्र और उसकी सामाजिक एकता की कीमत पर प्रसिद्धि, धन और शक्ति चाहते हैं। ये स्वार्थी लोग आरएसएस, पर्यावरण, राष्ट्र और विश्व को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले कई अन्य संगठनों के साथ ठीक यही कर रहे हैं। राष्ट्र को महान बनाने के लिए, एक लोकतंत्र को आलोचना, गहन विश्लेषण, राय और सुझावों की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि एजेंडा हानिकारक है और हमारे राष्ट्र के दुश्मनों का समर्थन करता है, तो नागरिकों को अधिक सतर्क और जागरूक होने की आवश्यकता है और प्रासंगिक और तथ्यात्मक जानकारी के साथ ऐसे झूठे आख्यानों का जवाब देना चाहिए। मुद्दा यह है कि क्या हमें उस संगठन पर भरोसा करना चाहिए जो दशकों से निःस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहा है या उस पार्टी पर जो संविधान को खारिज करती है। झूठे आख्यान गढ़ना सस्ता है। असली पत्रकारिता महंगी है। जनहित में महत्वपूर्ण नई जानकारी खोजना और उसे इस तरह से प्रासंगिक बनाना कि हम उसका उपयोग मानवीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कर सकें, पत्रकारिता का मुख्य कर्तव्य है। यह जनता के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने में बहुत मददगार हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य समग्र समाज में सुधार लाना होना चाहिए। जनता को विभिन्न प्रकार के आख्यानों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना समझ और विश्लेषण के उन पर प्रतिक्रिया देने से व्यवस्था, समाज और राष्ट्र पंगु हो जाते हैं। प्रत्येक समाचार या विमर्श का आदर्श वाक्य एकता और राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। हालांकि आरएसएस को उसकी अर्धसैनिक रणनीति और अनुशासन पर जोर देने के कारण कुछ लोग फासीवाद का भारतीय संस्करण मानते हैं। सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च के निदेशक क्रिस्टोफर जैफ्रेलॉट कहते हैं कि आरएसएस का दर्शन समाज को एक धर्मनिरपेक्ष जीव के रूप में देखता है, जिसकी भावना नस्ल के बजाय एक सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में निहित है और अंततः निरंतर जमीनी प्रयासों के माध्यम से इसे पुनर्स्थापित किया जाएगा। उनके अनुसार, आरएसएस की विचारधारा ने राज्य और नस्ल के सिद्धांत का निर्माण नहीं किया, जो नाजीवाद और फासीवाद जैसे यूरोपीय राष्ट्रवादों के प्रमुख कारक थे। इसके अतिरिक्त, वह इस बात पर जोर देते हैं कि आरएसएस नेताओं के लिए नस्लीय एकरूपता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी सांस्कृतिक एकता। राष्ट्र के पास एक ऐसा संगठन है, जो राष्ट्र के बारे में केवल सकारात्मक सोचता है और अपने नागरिकों को उनके व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए प्रशिक्षित करता है, साथ ही राष्ट्रीय आवश्यकताओं या आपदाओं की स्थिति में स्वयंसेवा करने के लिए भी तैयार करता है।

समस्या का समाधान नहीं पराली पर राजनीति

दंड की दस्तक के साथ धान की कटाई और पराली जलाए जाने के बीच आई दिवाली पर खतरनाक स्तर तक पहुंचे प्रदूषण के लिए फिर पराली को ही जिम्मेदार ठहराने में पंजाब और दिल्ली की राज्य सरकारें इस बार आमने-सामने रहीं। यह सच है कि पराली के चलते दोनों राज्यों के अलावा भी कई राज्य इसका प्रदूषण भुगत रहे हैं। लेकिन, ऐसा लगता है कि पंजाब-दिल्ली की सरकारें बजाय सुलह के एक-दूसरे को दोषी ठहरा, प्रदूषण से कैसे निपटेंगी। आसमान से निगरानी और लाइव तस्वीरों के इस दौर में भी सच सामने होने के बावजूद राजनीतिक बयानबाजी बेहद हैरानगी भरी है। सच है कि प्रदूषण की दमघोंटू हवा इसके प्रभाव में आने वाले हर किसी को तकलीफ देती है। यह भी सही है कि कोरोना के बाद बहुत से लोगों में प्रदूषण को बरदाश्त करने की क्षमता भी घटी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकारें बयानों से बचाव करें। हालांकि इस बार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की बात की जा रही है। देखना होगा कि यह तकनीक कितनी कामियाब होती है। लेकिन, प्रदूषण को लेकर यह स्थायी विकल्प हो पाए, ऐसा लगता नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते बरस दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण पर केंद्र को कड़ी फटकार लगाई तो पंजाब और हरियाणा सरकारों को भी चेताया। बावजूद इसके न काबू पाया जा सका, न ही कोई विकल्प खोजा गया। अदालत में तब पेश जवाब पर ही सवाल खड़े होना लाजिमी थे, जो हुए। फिलहाल दिल्ली में दिवाली के फौरन बाद प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक होना बहुत चिंताजनक है। 301 से ऊपर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (एएक्यूआई) इमरजेंसी स्थिति मानी जाती है। दिल्ली में 27 अक्टूबर तक प्रदूषण के स्तर में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन धान कटाई और पराली जलाने की घटनाओं में भी पंजाब व आसपास तेजी से स्तर कब कहां पहुंच जाए, कहना मुश्किल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि न केवल एनसीआर, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ा हुआ है। पंजाब भी बुरी तरह से इसकी गिरफ्त में है। लेकिन, यह सच है कि दिल्ली के मुकाबले वहां प्रदूषण अभी कम है। भले अभी पंजाब को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि लुधियाना में दिवाली के ठीक पहले 271, जालंधर में 247, अमृतसर में 224, पटियाला में 206 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़े, जो 27 अक्टूबर तक के हैं, देखने से पता चलता है कि दिल्ली में प्रदूषण में गिरावट के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 पर बना हुआ है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से 1900 प्रतिशत अधिक है। इसी दिन बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 से बढ़कर 387 हो गया है, जबकि दिल्ली सहित नौ शहरों में यह 300 के पार है। वहीं, देश में शिलांग की हवा सबसे साफ रही, जबकि भारत के 256 शहरों में से केवल 23 प्रतिशत में ही हवा साफ है यानी 77 प्रतिशत में हवा खराब है। गनीमत है कि बीच-बीच में बदलते मौसम से हालात इस बार पिछली बार जैसे नहीं बन पा रहे हैं। समझना होगा कि प्रदूषण के लिए केवल भारत ही नहीं पाकिस्तान की पराली का धुंआ भी जिम्मेदार है। नासा की एक रिपोर्ट, वर्ल्डव्यू एनिमेशन, सेटेलाइट तस्वीरें, चंडीगढ़ पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी के शोध से भी साफ हो गया है कि भारतीय पंजाब के मुकाबले पाकिस्तानी पंजाब में पराली ज्यादा जलती है। इस पर पड़ोसी पर भी लगाम की जरूरत है। आखिर कैसी कोशिशें हैं कि सालों साल से यह मसला बजाय सुलझने के हर बार नए आरोपों में घिर जाता है। रही बात सरकारों की तो केंद्र या राज्य की सरकारें किसानों को लेकर दावा कुछ भी करें, लेकिन किसानों की भी तो अपनी समस्याएं हैं। संसाधनों की कमीं से जूझते छोटे-छोटे किसानों को भला ऋण कैसे मिलेगा, ताकि पराली से विभिन्न उत्पाद बनाने वाली मशीनें खरीद सकें। किसानों की अपनी मजबूरी है। खेती मौसम पर निर्भर है और एक-दो दिन का बिगड़ा मौसम महीनों की मेहनत पर पानी फेर देता है। इसी चलते किसान भी तुरंत पराली जलाने को मजबूर होते हैं। किसान अगली फसल की बुवाई की जल्दबाजी मौसम के डर के बीच हालात से जूझता है। दूसरी फसल के लिए बहुत कम वक्त के चलते खासकर छोटे किसान असमंजस में जानते-समझते मजबूरन पराली जलाने का अपराध करते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण दशकों पुराना मुद्दा है। साल 1985 में भी आवाज उठी थी, जब कीर्ति नगर जैसे घने रिहायशी क्षेत्र में एक फटीलाइजर संयंत्र की जहरीली हवा से लोग बीमार होने लगे। तब अधिवक्ता एमसी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। हकीकत देखिए, सुनवाई के दौरान ही प्लांट से ओलियम गैस रिसी और तीस हजारी कोर्ट के एक वकील की जान चली गई। कइयों की हालत बिगड़ी। इसके बाद कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा। आबादी वाले क्षेत्र में क्लोरीन, सुपर क्लोरीन, ओलियम, फॉस्फेट जैसे जहरीले उत्पाद बनाने पर रोक लगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने को मौलिक अधिकार बनाया। धरातल पर देखें तो सिवाय कागजी योजना बनाने, बैठकें और आखिर में आरोप-प्रत्यारोप से ज्यादा भला अब तक क्या हासिल हुआ है। न तमाम प्रभावित राज्य सरकारें और न ही केंद्र, पराली के दूसरे उपयोग किसानों को समझा पाया। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश की बातें करने वाली दिल्ली सरकार भी खतरनाक स्तर तक प्रदूषण से फौरी राहत ही दिला पाई, जो कुछ देशों ने कर दिखाया। बजाय आपसी तू-तू, मैं-मैं के पराली संग्रहण, इसके व्यावसायिक उपयोगों पर पूरे साल चर्चा होती तो शायद जलाने की नौबत ही न आती।

Social Media Corner

सच के हक में...

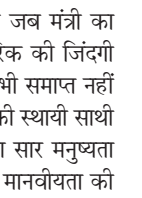

उन्नीसवीं सदी में बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में वंदे मातरम् का जो अमर गीत रचा वह 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय से जन-जन का प्रेरणा स्रोत बन गया। तब से ही, भारत माता की वंदना का यह गीत हमारे देशवासियों की भावनात्मक चेतना और एकता का उद्घोष बना हुआ है और बना रहेगा। स्वाधीनता के बाद देश ने राष्ट्र गीत के रूप में इसे सादर अपनाया। इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने के गौरवशाली अवसर पर हम सभी देशवासी यह दृढ़ संकल्प लें कि हम भारत माता को इस गीत की भावना के अनुरूप सुजला, सुफला और सुखदा बनाए रखेंगे। वंदे मातरम्।

(राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 'एक्स' पर पोस्ट)

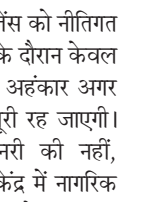

बिहार की हमारी बहनों और बेटियों का एनडीए में इसलिए अटूट भरोसा है, क्योंकि हमने उनके रोजगार और स्वरोजगार को लेकर कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। भभुआ के मेरे परिवारजनों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर बिहार के चुनावों में एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय पक्की कर दी है। बिहार में जंगलराज की वापसी के लिए राजद कितना बेचैन है, इसका पता चुनाव अभियान में वायरल हो रहे उसके गानों से चलता है। इनमें गरीब, दलित-महादलित और अति पिछड़े समाज के लोगों को डराने का प्रयास साफ नजर आता है। देश के गरीब और आदिवासी समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने कपूर्री ग्राम सहित बिहार के उन हिस्सों में भी सड़क से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक का विस्तार किया है, जो दशकों तक इनसे वंचित थे।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

घरेलू खपत बन रही बड़ा सहारा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और व्यापार तनाव के चलते वैश्विक वृद्धि दर धीमी रही, फिर भी मजबूत घरेलू खपत के दम पर भारत 6.6 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करते हुए दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक विकास दर की संभावनाएं रखता है। भारत की विकास दर चीन से भी अधिक अनुमानित है। इसी तरह एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की नई रिपोर्ट में कहा गया कि इस समय वैश्विक व्यापार की चुनौतियों और ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ के चलते भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर से मार्च के बीच तेज घरेलू खपत और सरकार का पूंजीगत व्यय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत सहारा बनता हुआ दिख रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि दीवाली पर बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही है। ई-कॉमर्स ने दमदार उछाल दर्ज की। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के कारण जीएसटी बचत उत्सव का परिदृश्य दिखाई दिया। महंगाई में कमी और जीएसटी की दरें घटना देश के बाजारों की तेज बढ़त के लिए एक बड़ा आधार हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 के दौरान खुदरा महंगाई घटकर 1.54 प्रतिशत रह गई। इससे पिछले महीने यह 2.07 प्रतिशत थी। यही खुदरा महंगाई दर सितंबर 2024 में 5.49 प्रतिशत थी। सितंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर आठ साल में सबसे कम रही और यह आरबीआई के अनुमानित लक्ष्य के भी निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ-साथ सितंबर में थोक महंगाई दर भी तेजी से घटकर 0.13 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। महंगाई दर घटने के साथ 22 सितंबर से जीएसटी सुधारों के लागू होने से इस बार दिवाली के त्योहारी बाजार में खरीदारी को पंख लगे। जीएसटी दरों के साथ-साथ आयकर में कटौती से लोगों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत प्राप्त हुई है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर 2025 में भारत का फाइनेंशियल वेलबीइंग इंडेक्स (एफडब्ल्यूबीआइ) 110.3 तक पहुंच गया है, जो वैश्विक औसत 103.6 से ज्यादा है। इसके साथ ही उपभोक्ता विश्वास भी पिछले साल से आठ अंक बढ़ा है, जो 2022 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। यह भी उल्लेखनीय है कि फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक जहां वर्ष 2023 में दीवाली के त्योहारी बाजार में 3.75 लाख करोड़ रुपये और वर्ष 2024 में 4.25 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी हुई थी, वहीं इस बार त्योहारी सीजन के तहत खरीदारी पांच लाख करोड़ रुपये के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने और अमेरिका में डालर की वैल्यू घटने से इस साल त्योहारी सीजन में चांदी और सोने के भाव भी रिकॉर्ड स्तर पर रहे और शेयर बाजार का ग्राफ भी बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार भी 700 अरब डालर के स्तर पर है। इस सबके परिणामस्वरूप इस समय औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर सर्विस सेक्टर तक मांग का बढ़ता हुआ नया अध्याय दिखाई दे रहा है। मांग और उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू खपत के साथ-साथ कुछ और आर्थिक अनुकूलताएं भी उभरती दिख रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने रूस और चीन के साथ आर्थिक-वैश्विक कूटनीति और नए निर्यात बाजारों में आगे बढ़ने की जो रणनीति अपनाई, वह कारगर होती दिखाई दे रही है। इस नीति से ट्रंप टैरिफ के बीच पिछले अगस्त और सितंबर माह में अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों में भारत के निर्यात बढ़े हैं। हाल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को ट्रंप के ऊंचे टैरिफ से हो रहे नुकसान की पूर्ति के लिए भारत के साथ रूस के व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिए हैं।

असमान वृद्धि

सितंबर माह के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े खासतौर पर उपयोगी हैं, क्योंकि ये इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही और पहली छमाही जैसी लंबी अवधि के बारे में जानकारियां मुहैया कराते हैं। खबरें तो बुरी नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर अर्धवार्षिक आधार पर देखा जाए, तो अप्रैल-सितंबर 2025 के आईआईपी के आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक विकास कम से कम पांच सालों में सबसे धीमा रहा। मात्र तीन फीसद की अर्धवार्षिक वृद्धि दर अपेक्षित वृद्धि से काफी कम है। हालांकि, तिमाही वृद्धि दशार्ती है कि हालात सुधर रहे हैं। दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 4.1 फीसदी रही, जबकि पहली तिमाही में यह दो फीसद थी। इस सबमें कम से कम सतही तौर पर सबसे अच्छी बात मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में हुई है। सितंबर माह में इसकी वृद्धि दर 4.8 फीसद रही, जो इस वित्तीय वर्ष में दूसरी सबसे ज्यादा है। तिमाही आधार पर जुलाई-सितंबर 2025 वाली तिमाही में मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में 4.9 फीसद की अपेक्षाकृत मजबूत वृद्धि देखी गई। यह दिसंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के बाद से सबसे तेज तिमाही वृद्धि है। अर्धवार्षिक आधार पर भी इस क्षेत्र की वृद्धि दर अप्रैल-सितंबर 2025 वाली छमाही में 4.1 फीसद पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल की पहली छमाही में यह वृद्धि दर 3.8 फीसद तक धीमी हो गई थी। खनन क्षेत्र में गतिविधियां सितंबर 2025 की दूसरी तिमाही के साथ-साथ वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में भी मद्धिम हो गईं। यूं तो इसके लिए कुछ हद तक इस साल के मानसून को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, फिर भी यह प्रदर्शन असामान्य रूप से खराब है। भारत की ऊर्जा और सामरिक खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की खातिर इस क्षेत्र को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

When the grand old centrist party moves to a side

The term 'ideology' has made a comeback to dominate the Indian public and political landscape in the last few years. It had become somewhat less fashionable since the early 1990s, but had a faint revival in 2014, when the Bharatiya Janata Party came to power. It found greater traction and mobility ever since the BJP sealed its dominance in 2019.

If ideology, as a somewhat rigid set or system of ideas, has seen a resurrection in more recent years, it can be argued that the reason is not the BJP, but the Congress. Since the Congress, under the leadership of Rahul Gandhi, began to perceive the BJP more as an intransigent ideological machine and less as a political opposition, it too began to devise a stubborn ideological response at the opposite end of the spectrum. From being a party with definite ideas and principles, it began to fancy being ideological. This response pattern has been a kind of global playbook, and therefore Rahul Gandhi definitely came before Zohran Mamdani; but, for distinct reasons, their levels of success have varied. Anyway, this ideological game witnessed a new flashpoint in the last few days. First, Priyank Kharge, son of Congress President Mallikarjun Kharge and a minister in Karnataka, wrote a letter to his own government demanding that the RSS's activities in public places and government premises be regulated, if not banned. Next, Kharge Senior took the idea to Delhi. On October 31, he asked for banning the RSS. The Congress seems to believe that to debilitate the RSS, often described as the ideological parent or mentor of the BJP, is to checkmate the saffron party. It may never have such a clear and straight outcome, but it is an assumption not without some logical basis. Interestingly, when Mallikarjun Kharge said he would prefer the RSS to be banned, he clarified that it was his "personal view". Kharge Senior may have appeared diffident and treaded cautiously, but the idea had become the party's mainstream opinion before he became the party's president. Rahul Gandhi's blunt assertions on the RSS and its mentors have often got him into legal trouble. In May 2022, he had said, "My fight is with the ideology of the RSS and BJP, which is a threat to our country. I fight against the hatred and violence these people spread." Again, in January 2023, he said he would never enter an RSS office, "I'll have to be beheaded before that. My family has an ideology." In Karnataka, this ideological battle finds new expression every now and then. In the latest round, the Congress government is allegedly allocating government land at subsidised prices to the Congress Bhavan Trust across the state in over a hundred places. When the BJP was in power in the state, it had allocated large tracts for its own party offices and to RSS's affiliate and sympathetic organisations. Now the Congress is doing something similar as an apparent ideological counter, although legally it may be in troubled waters. Interestingly, the Congress did not cancel the land allocation the BJP had made to itself and its affiliates; on the contrary, it made it an ideological raison d'être to allocate itself more land. This has been revealed in detail by The File, a site that uses RTI as its primary investigative tool.

Despite such ideological battles that the Congress endeavours to construct across the nation, ironically, the RSS and BJP have always visualised their mission as cultural and civilisational. They do not use the registers that overtly communicate an ideological strife. It is always about cultural and civilisational recovery, restoration and rebuilding.

G2 won't be music to India's ears

The new deal between the US and China is all about give and take

THE recent meeting between US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping in South Korea has been judged as a draw/ceasefire/truce in the long-term competition between the two world powers. From a situation suggesting decoupling, the relationship seems to have taken a 180-degree pivot. This seems to be a consequence of China besting the US in its trade negotiations.Trump termed the outcome of the meeting as scoring a hyperbolic 12 out of 10. US Secretary of War Pete Hegseth, who was in Kuala Lumpur for the ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus, tweeted after he met his Chinese counterpart Admiral Dong Jun, "I just spoke to President Trump and we agree — the relationship between the US and China has never been better".

Having spoken to Admiral Dong twice in a day to restore ties between the US and Chinese militaries, he declared that the tone had been set by Trump's "historic G2 meeting" and ended by noting "God bless both China and the USA!"He was echoing Trump's tweet posted hours earlier: "My G2 meeting with President Xi of China was a great one for both our countries. The meeting will lead to everlasting peace and success. God bless both China and the USA!"Both sides have pulled back from some of their more dire threats and actions. Effectively, they have kicked the can down the road by making their decisions valid for just the coming year. At another level, they seem to be trying to work out the framework in which G2, or a global US-China condominium, can operate.In his official tweet on the Dong Jun meeting, Hegseth noted the importance of maintaining a balance of power in the Indo-Pacific and US concerns about Chinese activities in the South China Sea and Taiwan.In the Phase I trade deal that China signed with the US during Trump's first term in 2020, Beijing was forced to make unilateral commitments to buy American products. But the current deal is all about give and take.

The US backed off from its new Entity List export restrictions in exchange for China doing so with its rare earths rules. The Entity List rule was unveiled on September 29, barring Chinese firms at least 50 per cent owned by previously sanctioned Chinese companies from receiving restricted US tech exports using subsidiaries. What it did was to effectively increase the number of Chinese firms on the Entity List from 1,400 to a massive 20,000.This had led China to use its brahmastra of rare earths on the eve of the Xi-Trump meeting. Under this rule, export controls would kick in even if 0.1 per cent of the product used Chinese rare earth processing technologies anywhere in the world. This virtually covered almost all smartphones, hard drives, TVs, motors and medical devices in the world.The Chinese also agreed to resume soyabean purchase, much to the relief of Trump, whose farmer support base was becoming increasingly restless over the Chinese decision not to buy American soyabean. The US suspended the implementation of measures under its Section 301 investigation targeting China's maritime logistic and shipbuilding industries for a year.

The US will now drop its overall tariff rate for China to 47 per cent. This is, in effect, where it was before Liberation Day, April 2. If we take the 20.7 per cent tariff that existed before Trump assumed office and add 10 per cent of the reduced fentanyl tariff, we are left with just 10 per cent additional tariff which was the baseline figure applicable to all.Both sides have agreed to cooperate on the fentanyl issue, but there are other matters that need to be resolved, such as Chinese access to Nvidia chips and the ownership of TikTok. The Taiwan issue seems to have been sidestepped for the present.A major reason for China's success has been tactics. While Beijing systematically prepared for a possible clash in the last few years, Trump led Washington to hit out recklessly on the tariff issue. Instead of targeting China alone, as it had done in 2020, the US sharply escalated the fight with China and hit the whole world with its Liberation Day tariffs, alienating friends and allies.

To an extent, this was also an underestimation of Chinese developments in recent years. There was a belief that the American economy, with the help of artificial intelligence (AI), had gained a decisive edge, while Covid-19 travails, economic slowdown, unemployment and military purges had weakened China.

The détente, which now seems to be verging on an entente, has brought a sense of relief around the world. A US-China implosion would have had consequences for the entire global economy. But the developments should not generate a false sense of security. Despite Trump's and Hegseth's effusive take on the China relationship, the reality is that there have been too many recent ups and downs to predict a stable future.

One thing is clear: the threatened decoupling of the Western and Chinese economies is not around the corner. The race now is for global leadership amidst some shaky guardrails between the G2. Here, while the US has been seeking ephemeral gains through tariffs, the Chinese are preparing for another future. Their latest five-year plan focuses on quantum technology, bio-manufacturing, hydrogen energy and nuclear fusion. China already leads in some of these fields, but the US remains ahead overall and has placed its current bets on AI.The economic and geopolitical consequences of competitive US-China relations in these areas are hard to forecast. But they cannot be particularly comforting for countries like India that had counted on the US to maintain geopolitical heft against China.

To make our streets safer, follow Supreme Court order on strays

At the heart of the hatred for animals lay fear and the conflict over sharing habitats in a rapidly urbanising ladscape

Life is cheap in the animal world. In Bengaluru, a caretaker recently slammed a chihuahua to death in an apartment lift; during Diwali, some miscreants tied crackers to a dog's legs and exploded them, while others stuffed a dog's mouth with fireworks and set them alight. In our anthropocentric world, horror stories of animal abuse pop up regularly. This happens even after activists have brought about a major shift in laws to curb animal cruelty—under Section 325 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, killing or maiming an animal attracts five years in prison, a penalty, or both. However, the provision is observed more in breach.

At the heart of the hatred for animals lay fear and the conflict over sharing habitats. Chilling incidents of packs of dogs mauling children and senior citizens, and rising cases of rabies have made them targets. This August, a Supreme Court bench stayed another bench's decision to move all strays in the National Capital Territory into shelters after a petition showed it ran counter to the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2023; instead, it ordered all states and Union Territories to report back after creating dedicated feeding spaces for strays. When none did, in a rare move earlier this week, the top court summoned and upbraided all the chief secretaries, who tendered an unconditional apology.The act of feeding street dogs itself sparks a furious debate in cities. While animal lovers claim it blunts aggressive canine behaviour, others warn it increases the menace. The Bengaluru authorities' plan to provide one nutritious meal a day at designated feeding locations for the city's street dogs—a step farther than the Supreme Court's order—can put the debate to rest. It can prevent dogs from forming aggressive packs to hunt for food. Revitalised vaccination and sterilisation programmes, which suffered during and after the pandemic, will also help. Maintaining demarcated habitats for larger animals is itself proving to be a tough ask for governments at a time human habitats are expanding and animal conflicts are on the rise. At least in our cities, we will have to come to terms with the fact that dogs are here to stay. The Supreme Court's order, itself the result of a careful consideration of the dangers, cannot be wished away. In its spirit, the motto should be to live and let live.

Stillness of the discerning in Bihar

For a state whose told stories have travelled the arc from chaos to order and back through impossible political contortions, a known form of stability still commands an instinctive nod.

Bihar has never been short of noise. Certainly not when it mattered. Its politics has marched through history with a daring swagger — JP's call that shook New Delhi, Mandal's churn that redrafted power, the long years of Lalu raj that jolted the old order. Even the subtler Nitish era made bold strokes on the canvas, turning India's polity yet again with the caste census narrative and grand alliance politics.Yet this election arrives on soft feet. On November 5, the campaign for the first stretch of 121 constituencies is winding down, and the battle for the remaining 122 — those border districts where sentiment often travels across rivers and frontiers — will begin soon. And through it all, there hangs a curious quiet.Whether in Nitish Kumar's native Bakhtiyarpur, or hamlets like Gauspur and Chitapur fringing Patna, whether in Dalit 'tolas' where caste is still geo-tagged or along the mobile 100-km sweep to Gaya on NH-22, out in villages like Barachati and Tekari near where a legend named Dashrath Manjhi once moved mountains, the stillness is audible.Even in places like Mokama where bullets flew the other day, or Barh, which saw fisticuffs after this writer left, the action is all on one slim band where politics does its business. The people seem unmoved. Almost cold.

This is not indifference. It is an extended pause — a thinking state, perhaps it's the hush of crores of people thinking harder.The old Bihar election grammar is still here: the woven caste alliances, the search for the right symbol atop the right community, the deft stitching of booth workers and social equations. But listen closely, and the dialogues are shifting pitch.

It is no longer enough to promise representation; people want opportunity. Bihar's young — impatient, painfully aware of the ticket-to-life stamped "migration" that's been their lot for years, and now uniformly literate about the ways of the world beyond their panchayat WhatsApp group — are asking sharper questions.Identity of the other sort has not dissolved; only its fabric has thinned in the face of this new common identity, an identity of experience. Numbers are never incidental here. OBCs and EBCs together form roughly two-thirds of Bihar — a demographic truth that still underwrites strategy.

Yadavs remain the single biggest OBC bloc, Kurmis and Kushwahas count in pockets where one village's mood can bend a seat, Dalits and Mahadalits together hold a weight politicians can never ignore, and the elite castes — though numerically modest — continue to influence candidate choice and the political discourse, particularly in the plains

Bihar has chosen reflection over rhetoric for now

Tejashwi Yadav stands at the pivot of this transition—bearing a surname thick with history, and yet determined to build a politics whose vocabulary begins not with past entitlement but future dignity.His rallies have energy, his phrasing has a way of finding the young and speaking to them. In the village alleys, you hear a new sentence: "Chance toh milna chahiye." A chance must be given.

Across the aisle, Nitish—visibly ageing, visibly weary—remains, remarkably, a comfort choice. This is something adjacent to loyalty; more like habit, the trust evoked by an old armchair.

For a state whose told stories have travelled the arc from chaos to order and back through impossible political contortions, a known form of stability still commands an instinctive nod.

His alliance with the BJP brings an electoral machine that can calculate with the cold precision of algorithms. But the BJP's quiet ambition glimmers beneath its dutiful partnership: a desire, someday, to govern Bihar not by the consent of allies but on its own steam.The Congress lingers at the edge—a memory, a partner, a seeker of relevance in a landscape it once defined and now must negotiate seat by seat.Thus Bihar stands at a crossroads marked not by fury but by thought. The shouting has dimmed. The electorate may not be bored or disinterested, it is discerning. A state long animated by political passion has chosen—at least for this moment—reflection over rhetoric. In a pause.

Still waters do run deep. Bihar may simply be listening to itself before it speaks again.

Sensex, Nifty tumble in early trade dragged by foreign fund outflows, weak global peers

New Delhi.(Agency)

Benchmark indices Sensex and Nifty tumbled in early trade on Friday as relentless foreign fund outflows and weak trends in global markets hit investors' sentiment.The 30-share BSE Sensex tanked 631.93 points to 82,679.08 in early trade.

The 50-share NSE Nifty declined 184.55 points to 25,325.15.From the Sensex firms, Bharti Airtel, HCL Tech, Tech Mahindra, NTPC, Tata Consultancy Services and Maruti were among the biggest laggards.

However, ITC, ICICI Bank, Eternal and Power Grid were among the gainers.In Asian markets, South Korea's Kospi, Japan's Nikkei 225 index and Hong Kong's Hang Seng index traded sharply lower.

Shanghai's SSE Composite index quoted marginally down.US markets ended significantly lower on Thursday.Foreign Institutional Investors (FIIs) offloaded equities worth Rs 3,263.21 crore on Thursday, however, Domestic Institutional Investors (DIIs) bought stocks worth Rs 5,283.91 crore, according to exchange data.

"A significant feature of the present market trend is that despite the DIIs buying far more than what the FIIs are selling (Rs 5,283 crore DII buying vs Rs 3,263 crore FII selling yesterday) the market continues to drift down.

The huge shorting by FIIs are overpowering the DII and investor buying in the market."The success of the FII strategy of sustained selling in India and moving money to cheaper markets has emboldened them to continue the strategy and continue shorting the market.Short covering can lead to trend reversal but there are no immediate triggers for that in sight.But markets have an uncanny ability to surprise," V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments Limited, said.Brent crude, the global oil benchmark, climbed 0.30 per cent to USD 63.57 per barrel.

Why urban millennials are renting lifestyle products instead of buying them

New Delhi.(Agency)

For urban millennials, the idea of ownership is quietly losing its shine. From furniture to gadgets and even fashion, a growing section of young city dwellers are choosing to rent instead of buy. It's not a passing trend — it's a lifestyle shift powered by flexibility, rising costs, and changing ambitions."Urban millennials are choosing to rent over ownership because they prioritise flexibility and low-commitment living," says Neha Mohhata, CEO and co-founder of Brize. "People have become smart. They ask why invest in depreciating assets when you can rent and upgrade without worry?"

Her words reflect a larger cultural rethink. Millennials today are no longer obsessed with collecting assets — they want experiences, mobility, financial breathing room, and fewer long-term ties.

FLEXIBILITY OVER PERMANENCE

From job hopping to co-living spaces and compact apartments, urban life is constantly shifting — and so are the needs that come with it."As millennials change jobs or move to smaller homes, they prefer renting products that are light and easy to move," Mohhata explains. Owning bulky furniture or expensive appliances no longer fits the lifestyle of a generation that may change cities within months.

For many, the appeal lies not just in saving money, but in escaping the stress around maintenance. Broken AC? Faulty coffee machine? With rentals, someone else handles it.

IS IT AFFORDABILITY OR MINDSET? THE ANSWER IS BOTH

Rising prices, EMIs, and daily expenses have made big purchases harder to justify — but millennials are also rethinking the psychology of ownership itself."This shift is driven by both affordability and evolving attitudes," says Mohhata. "People now value using things over owning them. Renting lets them avoid depreciation, maintenance, and storage challenges."

Planning voluntary retirement under UPS? All you need to know

New Delhi.(Agency)

The Department of Pension and Pensioners' Welfare (DoPPW) has issued guidance on voluntary retirement rules under the Unified Pension Scheme (UPS) for central government employees. With the November 30, 2025 deadline approaching to opt into UPS under the National Pension System (NPS), the government wants to remove confusion and lay out the process in plain terms.

The latest circular focusses on who can take voluntary retirement, how much notice must be given, whether the decision can be reversed, and how pension will be calculated.

WHO CAN TAKE VOLUNTARY RETIREMENT UNDER UPS?

Under Rule 13 of the UPS regulations, any central government employee who has completed 20 years of regular service can apply for voluntary retirement (VRS). This applies only to those who have opted for UPS under NPS.

This means employees cannot seek VRS under UPS unless they have served the minimum required period of 20 years.

NOTICE PERIOD: 3 MONTHS, BUT RELAXATION POSSIBLE

An employee wanting to take VRS must submit a written notice of at least three months to the appointing authority.However, there is flexibility. The appointing authority can shorten the notice period if early retirement does not disrupt office work or create administrative issues. This decision is taken on a case-by-case basis.

RBI's M&A funding move aimed at boosting real economy: Governor Malhotra

New Delhi.(Agency)

The regulatory move to allow banks to fund mergers and acquisitions is aimed at supporting the real economy, Reserve Bank Governor Sanjay Malhotra has said.

Last month, the RBI announced a raft of measures and intentions, including allowing banks to fund domestic acquisitions, permitting foreign borrowings for the real estate sector, and raising the cap on loans for buying shares through IPOs. These steps were part of broader efforts to boost bank lending in Asia's second-largest economy.

"These measures come, as you are aware, with guardrails—such as limiting bank funding to 70% of the deal value and setting limits on the debt-to-equity ratio—which will ensure safety while allowing banks and their stakeholders to benefit from additional business," the RBI chief said while addressing a State Bank event in Mumbai on Friday.

Stating that the RBI is moving with caution, Malhotra said the need for courage had prompted the easing of bank norms. He made it clear that while the Reserve Bank continues to act cautiously, the decision to relax certain regulations reflects a willingness to display courage in policy reform.The liberalisation of external commercial borrowing (ECB) norms, he said, comes amid a strengthening external sector and strong capital inflows, describing it as a "natural step" in the country's financial evolution.

According to Malhotra, RBI projections indicate that capital flows will remain "quite strong" for the remainder of the fiscal year.

On the move to allow real estate companies to borrow from abroad, the governor clarified that the ECB route will be permitted only for projects compliant with foreign direct investment (FDI) norms and will remain prohibited for speculative activities or land purchases.He added that the RBI is striving to make rule-making more open, data-driven, and evidence-based, following public consultations and impact assessments.Malhotra emphasised that the higher responsibilities now placed on banks stem from their improved performance and governance, noting that the central bank has sufficient tools to rein in any errant behaviour.He further said that the RBI does not wish to micromanage, as no regulator can or should substitute for boardroom judgment. Each case, he stressed, must be assessed on its own merit."We need to allow regulated entities to take decisions based on the merits of each case, rather than prescribing a one-size-fits-all rule," he reiterated.Since assuming office, Malhotra has underscored the importance of simplifying regulations to improve ease of doing business, while also accounting for the cost of regulation before introducing new measures."While we move with caution, we need to display courage," he said, explaining the rationale.

Tesla shareholders approve Elon Musk's $1 trillion pay package

Mumbai.(Agency)

Tesla shareholders on Thursday overwhelmingly endorsed a massive pay package for CEO Elon Musk that could reach $1 trillion.The pay package, crafted to ensure Musk's continued service to Tesla as the company pursues breakthrough technology on artificial intelligence and robotics -- won more than 75 percent support from shareholders, a Tesla official said at the company's annual meeting.

"I'd like to just give a heartfelt thanks to everyone who supported the shareholder votes," a euphoric Musk told the gathering. "I super-appreciate it."Cheers of "Elon" broke out after the vote result was announced at the gathering, which was held at the company's factory in Austin.

Musk has emerged as a lightning rod figure, in part due to his embrace of right-wing politicians including President Donald Trump. But Thursday's vote marked the latest demonstration of the entrepreneurial billionaire's resonance with investors.

The package aims to ensure Musk stays at Tesla for at least seven-and-a-half years. It would lift Musk's holding in Tesla from about 12 percent when the package was introduced in September to potentially more than 25 percent.

Musk has described Tesla's potential growth as nearly boundless, saying in July that it "will be the most valuable company in the world by far" if it delivers on envisioned advances on autonomous driving and AI.

But Musk himself has hinted he could leave Tesla or take a back seat if his ownership share is not raised enough to give him the influence over its future that he desires.In urging shareholders to back the proposal, Tesla Chair Robin Denholm argued keeping Musk was essential to Tesla's future, warning the company's stock could dive if he exited.The board has shrugged off criticism that the billionaire's embrace of contentious political figures has weighed on sales.

Lenskart IPO listing next week: Will it deliver profits or disappoint?

New Delhi. (Agency)

Lenskart's much-awaited IPO is set to make its market debut on Monday, November 10, with investors closely watching whether the eyewear company can deliver listing gains after days of sharp movement in its grey market premium (GMP).Lenskart IPO received a strong response from investors, was subscribed 28.27 times overall, indicating robust demand across categories.The IPO opened on October 31 and closed on November 4. The allotment was finalised on November 6, and those who applied for shares can now check their status on the BSE website or the registrar's portal, MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Pvt Ltd).

However, the optimism that followed the heavy subscription has been fading in the grey market.

The GMP, which reflects the premium investors are willing to pay for unlisted shares, has dropped significantly over the past week. On October 31, the GMP stood at Rs 95, implying a strong potential listing gain of 23.63%.

It later fell sharply to Rs 85 on November 1, Rs 59 on November 3, and continued to slide to Rs 10.5 as of November 7. Based on this latest GMP, the estimated listing price is around Rs 412.5, indicating a modest 2.61% gain over the issue price of Rs 402.Despite the muted short-term outlook, analysts remain cautiously optimistic about Lenskart's long-term prospects.

Shivani Nyati, Head of Wealth at Swastika Investmart, said that Lenskart is India's largest organised eyewear retailer and has a strong omni-channel business model combining online and offline presence."The eyewear market in India is growing fast, offering a strong opportunity for expansion. While the IPO has been heavily oversubscribed, the grey market premium has cooled from very high levels to a modest 2-3%. Given the steep valuation, much of the value will depend on post-listing execution not just a strong "listing pop," she added.

OpenAI faces seven lawsuits claiming ChatGPT drove people to suicide, delusions

New Delhi.(Agency)

OpenAI is facing seven lawsuits claiming ChatGPT drove people to suicide and harmful delusions even when they had no prior mental health issues.The lawsuits were filed Thursday in California state courts allege wrongful death, assisted suicide, involuntary manslaughter and negligence. Filed on behalf of six adults and one teenager by the Social Media Victims Law Center and Tech Justice Law Project, the lawsuits claim that OpenAI knowingly released GPT-4o prematurely, despite internal warnings that it was dangerously sycophantic and psychologically manipulative.

Four of the victims died by suicide.

The teenager, 17-year-old Amaurie Lacey began using ChatGPT for help, according to the lawsuit filed in San Francisco Superior Court. But instead of helping, "the defective and inherently dangerous ChatGPT product caused addiction, depression,

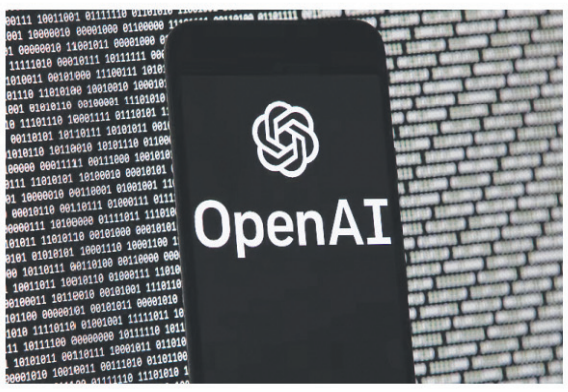

and, eventually, counseled him on the most effective way to tie a noose and how long he would be able to "live without breathing.""Amaurie's death was neither an accident nor a coincidence but rather the foreseeable consequence of Open AI and Samuel Altman's intentional decision to curtail safety testing and rush ChatGPT onto the market," the lawsuit says.OpenAI did not immediately respond to a request for comment Thursday.

Another lawsuit, filed by Alan Brooks, a 48-year-old in Ontario, Canada, claims that for more than two years ChatGPT worked as a "resource tool" for Brooks.

Then, without warning, it changed, praying on his vulnerabilities and "manipulating, and inducing him to experience delusions. As a result, Allan, who had no prior mental health illness, was pulled into a mental health crisis that resulted in devastating financial, reputational, and emotional harm."

ED makes third arrest in Rs 68 crore fake bank guarantee case linked to Reliance Power

Amar Nath Dutta was arrested on Thursday under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) and remanded to four days of Enforcement Directorate custody.

New Delhi.(Agency)

The Enforcement Directorate (ED) has made a third arrest in connection with a money laundering investigation involving businessman Anil Ambani's group company, Reliance Power. The probe pertains to the issuance of an alleged fake bank guarantee worth Rs 68 crore, official sources said on Friday.A man identified as Amar Nath Dutta was taken into custody on Thursday under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). A special court subsequently remanded him to four days of ED custody, the sources added.

Earlier, the agency had arrested former Reliance Power Chief Financial Officer (CFO) Ashok Kumar Pal and Partha Sarathi Biswal, Managing Director of Odisha-based Biswal Tradelink, in connection with the same case.The investigation concerns a bank guarantee of Rs 68.2 crore submitted to the Solar Energy Corporation of India Limited (SECI) on behalf of Reliance NU BESS Limited, a subsidiary of Reliance Power, a listed company, which was later found to be "fake". The company was formerly known as Maharashtra Energy Generation Limited.

According to the ED, Biswal Tradelink was allegedly operating a racket providing fake bank guarantees to various business groups.The Reliance Group has clarified that Anil Ambani "has not been on the Board of Reliance Power Limited for more than three and a half years and is not concerned with this matter in any manner."The money laundering case stems from a November 2024 FIR filed by the Delhi Police's Economic Offences Wing (EOW). It was alleged that Biswal Tradelink issued fake bank guarantees for a commission of eight per cent.

Investigations revealed that Reliance NU BESS Ltd. had submitted a bank guarantee purportedly issued by FirstRand Bank, allegedly located in Manila, Philippines. However, the said bank does not have a branch in that country, according to the ED.

Reliance Power earlier stated that it was a "victim of fraud, forgery and cheating conspiracy" in this case and had made due disclosures to the stock exchanges on 7 November 2024. A company spokesperson added that a criminal complaint had been lodged with the Delhi Police's EOW in October 2024 against the third-party accused company, and that the "due process" of law would follow.

The ED further claimed that Biswal Tradelink used a deceptive email domain, s-bi.co.in, closely resembling the official State Bank of India domain sbi.co.in, to create a "facade" of authenticity in its communications with SECI.Investigators also found that Biswal Tradelink was a "mere paper entity", with its registered office located at a residential property belonging to one of Biswal's relatives.

India fortifies Chicken's neck: 3 new garrisons set up on Bangladesh border

►India has fortified its eastern border by establishing three new military garrisons along the Indo-Bangladesh frontier to secure the strategic Siliguri Corridor amid shifting regional alliances. This move aims to enhance surveillance and rapid response capabilities in a sensitive area connecting mainland India to its northeast states.

Agency New Delhi.

India has strengthened its eastern frontier by setting up three new fully operational military garrisons along the Indo-Bangladesh border, at Bamuni (near Dhubri), Kishanganj, and Chopra, to secure the strategic Siliguri Corridor, commonly known as the "Chicken's Neck".According to top intelligence sources, the move is part of a broader plan to plug tactical gaps, enhance surveillance, and boost rapid-response capabilities in one of India's most sensitive regions.

The Siliguri Corridor, a 22-kilometre-wide strip in North Bengal, connects the rest of India with its seven northeastern states and lies sandwiched between Nepal, Bhutan, Bangladesh, and China.

INDIA ON GUARD AS DHAKA REORIENTS POLICY

The development comes amid reports of increased engagement between Bangladesh's interim Chief Adviser Muhammad Yunus and Pakistan's military establishment, including a recent meeting with Pakistan's Joint Chiefs of Staff Chairman General Sahir Shamshad Mirza, reportedly to discuss connectivity and defence cooperation.Since Yunus took charge following former Prime Minister Sheikh Hasina's ouster, Bangladesh's policy direction has undergone a marked shift, with overtures to China for investments and a reset of ties with Pakistan. Intelligence assessments describe this as part of a strategic attempt to "reshape the power balance" in the eastern neighbourhood, potentially affecting the security of the Siliguri Corridor.

'CHICKEN'S NECK IS OUR STRONGEST LINK'

Contrary to perceptions of vulnerability, senior Indian military officials have emphasised that the region is India's "strongest defence corridor."

An Army source said, "The Siliguri corridor is under multi-layered security cover. The new garrisons will enhance our quick mobility, logistics, and real-time intelligence integration."Earlier, the Indian Army Chief had remarked, "As far as the Chicken's Neck is concerned, I see it from a different perspective. It is our strongest region because our entire force deployed in West Bengal, Sikkim and the Northeast.

Congress's Bhupinder Hooda to face trial in land scam case as court rejects plea

Agency New Delhi.

Former Haryana Chief Minister and Leader of Opposition Bhupinder Singh Hooda will now stand trial in the alleged Manesar land scam case after the Punjab and Haryana High Court dismissed his petition challenging the proceedings.The order cleared the way for a Central Bureau of Investigation (CBI) special court in Panchkula to frame charges against Hooda and others in connection with the alleged scam. The CBI had already filed a detailed chargesheet in the case, naming Hooda among 34 accused.

The central agency's probe began in 2015 following Supreme Court directions, and culminated in a nearly 80-page chargesheet submitted in 2018. The court will now proceed with framing charges, paving the way for a full-fledged trial.

The case dates back to 2005, when Hooda, as Chief Minister, issued a Section-6 notification to acquire land in Manesar for an Industrial Model Township. Compensation was fixed at Rs 25 lakh per acre, and a notice under Section-9 followed soon after.

However, between 2005 and 2007, several builders allegedly bought around 400 acres from farmers at throwaway prices, anticipating the acquisition. The then state government, under Hooda, later released the land from acquisition in 2007, which officials said caused a loss of nearly Rs 1,500 crore to farmers.

In its earlier ruling, the Supreme Court had described the Hooda government's decision to cancel the acquisition as 'malafide' and amounting to fraud. It directed the CBI to investigate the "undue gains" made by middlemen and ensure that every penny was recovered by the state.

With the High Court's dismissal of the Congress leader's plea, Hooda will now face trial before the CBI special court.

Delhi: Rat droppings in mid-day meal flour at Narela kitchen, probe ordered

Agency New Delhi.

Rat droppings in wheat flour, expired salt, tobacco packets, and a foul stench of rot: that is what Municipal Corporation of Delhi (MCD) officials found during a surprise inspection at a Narela kitchen supplying mid-day meals to over 20,000 schoolchildren.The kitchen, run by the Dalit Manav Utthan Sansthan (DMUS), had been flagged for similar violations in 2023 as well, when the then deputy director of education recommended its blacklisting. However, no action was taken, and the NGO continued to feed thousands of children across MCD schools. The MCD has formed an enquiry committee to probe the workings of the kitchen and submit a report in seven working days.

Amit Kharkhari, vice chairman of the MCD Education committee, who conducted the inspection on Tuesday, told this newspaper, "We received complaints about kitchen, following which I went for a surprise inspection. This kitchen caters to over 20,000 schoolchildren in MCD schools and Anganwadi centres." This kitchen has two other branches in other zones as well, which we are yet to be inspected by the MCD.

Kharkhari was disappointed with the hygiene condition in the kitchen. "It was shocking to see gutka packets lying in the middle of the kitchen where food was prepared, and then there were rat droppings all over," he said. "We will take further action in this matter after receiving the committee's report," he further said.

Currently, there are 15 kitchens in Delhi which serve mid-day meals in MCD schools and Anganwadi centres.In 2023, the Department of Women and Child Development had issued an order stating that the DMUS had been delivering inadequate supplies of weaning food to Anganwadi centres and was leaving vulnerable sections, like pregnant women, lactating mothers, and children, deprived of supplementary nutrition.In the same year, the department had again flagged the performance of the organisation and issued a show-cause notice, saying that the performance of the DMUS had been non-satisfactory and it had not met the expected standards in providing adequate and timely supply of supplementary nutrition.

BJP sent voters to Bihar in large numbers: AAP's 3 big expose on vote chori

Agency New Delhi.

Aam Aadmi Party (AAP) leader Saurabh Bharadwaj has turned up the political heat ahead of the second phase of Bihar Assembly elections, releasing a series of videos on social media accusing the Bharatiya Janata Party (BJP) of orchestrating a "massive voter fraud" by transporting voters from other states to cast ballots in Bihar.In a dramatic social media campaign branded "Vote Theft", the Delhi AAP chief claimed that the BJP had systematically identified its loyal voters during the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and ensured their names were not deleted in Delhi or Haryana.

According to him, these same voters were later sent to Bihar on special trains arranged by the party, complete with tickets and logistics handled by BJP functionaries.

"The BJP identified voters during the SIR and made sure their votes weren't deleted. Then lakhs of such voters were sent to Bihar before the elections, all arrangements made by the BJP," Bharadwaj alleged in his posts, sharing the videos, citing footage from

YouTube channels.In another post, he pointed to visuals from Karnal railway station, claiming the local BJP district president was seen supervising the departure of voters to Bihar. "This is not just manipulation, this is organised theft of democracy," he said.

Bharadwaj further questioned the operation of "special trains" run in the name of Chhath Puja, suggesting that their real purpose was political."If these trains were for Chhath, why are they still being sent after the festival? The reason is simple, Bihar elections. Government machinery and public money are being used to buy democracy," he said.

The first phase of Bihar elections was held on Thursday, with voter turnout reportedly reaching one of the highest levels in decades.Yesterday, Bharadwaj alleged that some BJP leaders, including Rajya Sabha MP Rakesh Sinha and Delhi BJP Purvanchal Morcha president Santosh Ojha, had cast votes in both Delhi and Bihar, despite the Election Commission's claim of eliminating duplicate entries from the rolls.

Why Dreamliner Crash Probe Is A Struggle Between Science And Emotion

Agency New Delhi.

The Supreme Court's comments today, which gave comfort to the father of the pilot-in-command of Air India's Boeing 787 Dreamliner that crashed in Ahmedabad, has brought the focus back on theories of electrical malfunction and other probable causes.

No one can blame the pilot of the Dreamliner for the crash in June that killed 260, the Supreme Court told the pilot's father today and sent notices to the Centre, the civil aviation regulator (DGCA), and the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB).

The order came on a petition by Pushkaraj Sabharwal, whose son Sumeet Sabharwal was the pilot-in-command of the Boeing 787 Dreamliner, seeking an independent judicial probe into the crash. Justice Surya Kant, who heard the petition, told the 91-year-old grief-stricken father of the late pilot, "This crash was

extremely unfortunate, but you should not carry this burden that your son is being blamed."The AAIB in its preliminary report released in July said fuel supply to both engines was cut off shortly after takeoff. The two fuel control switches were moved to the "cutoff" position in quick succession; although the switches were turned back on about 10 seconds later, the engines had already flamed out, leading to the crash, the report said.

The court's observations come at a time when there are credible theories from experienced aviation experts pointing to the possibility of a massive electrical short circuit caused by water ingestion in one of the bays of the Boeing 787.This, the theories suggest, resulted in a cascading set of failures causing the logic in the aircraft's systems to shut down fuel flow to the engines of the Dreamliner as a safety feature, albeit one that eventually resulted in the crash of the aircraft - since there was no time, altitude or airspeed for the engines .

Supreme Court to hear DMK's plea against 'unconstitutional' SIR in Tamil Nadu

The DMK's plea has termed the exercise as being violative of Articles 14, 19 and 21 (right to equality, freedom of speech and right to life) and other provisions of the Constitution and the Representation of People Act and the Registration of Electors Rules of 1960.

Agency New Delhi.

The Supreme Court on Friday said it would hear on November 11 petitions filed by Tamil Nadu's ruling DMK party and civil society group Association of Democratic Reforms (ADR) challenging the Election Commission of India's (ECI) move to carry out a Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.The latest petitions come as the top court is already hearing pleas challenging the validity of the poll panel's decision to conduct the SIR exercise in Bihar, where the first phase of Assembly polls were conducted on Thursday, with the final phase scheduled for November 11.

During the hearing today, senior advocate Vivek Singh, appearing for the DMK,

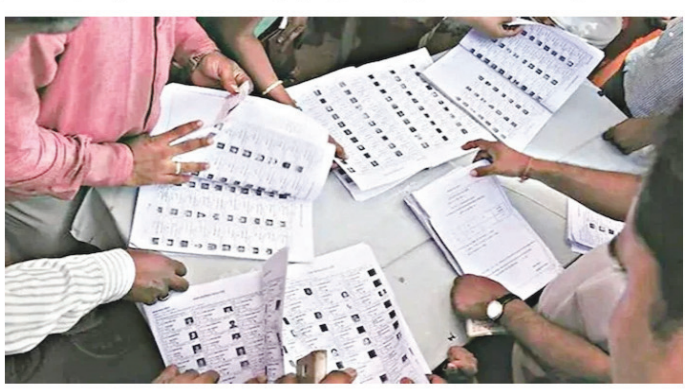

urged the bench comprising Chief Justice of India BR Gavai and Justice K Vinod Chandran to urgently take up the party's petition for deliberation."We have also sought an urgent stay on the process," he said.The DMK's plea has termed the exercise as being violative of Articles 14, 19 and 21 (right to equality, freedom of speech and right to life) and other provisions of the Constitution and the Representation of People Act and the Registration of Electors Rules of 1960.

"Issue a writ of certiorari calling for records pertaining to the order dated October 27, 2025 of the respondent directing that a Special Intensive Revision be conducted in the state of Tamil Nadu," it added.

In response, the Chief Justice said, "List the matter for Tuesday (Novermber 11)."

Earlier this week, RS Bharathi, organising secretary of the DMK, approached the top court against the SIR, calling the exercise "unconstitutional, arbitrary, and a threat to democratic rights".

Meanwhile, another Supreme Court bench comprising Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi agreed to hear a bunch of anti-SIR petitions from November 11 onwards after advocate Prashant Bhushan, appearing for the Democratic Reforms, said the exercise "goes to the root of democracy".

Bhushan said the urgency of the matter is because the SIR exercise is being conducted across 12 states and Union Territories from November 4 to December 4.

"Photo Was Mine But Name Was Someone Else's": Haryana Voter On Fraud Row

New Delhi. (Agency)

The controversy over Rahul Gandhi's 'H-bomb' – renewed allegations of centralised voter fraud involving the Election Commission and the ruling BJP – rolled on Friday with NDTV talking to another voter whose photographs appeared against multiple voter IDs, 223 in this case.

The voter in this case is 75-year-old Charanjit Kaur, who lives in Dhakola village in Haryana's Ambala district. Kaur told NDTV she voted – in last year's Assembly election – just once.

She also said everyone told her photo had been displayed on several voter ID cards. "When I went to cast my vote, the photo (on the list) was mine but it was against someone else's name," Kaur said.

"I told my son about it," she told .Her son, Tejinder Singh, who contested the village sarpanch election, said he filed a complaint with officials, stating his mother's photo had been placed in multiple lists but with incorrect names and addresses. It seemed to be a printing mistake, he said, but no action was taken.

In Malikpur village in Sonipat district, for example, several voters - including four members of one family - mysteriously disappeared from the list. One voter, Anjali Tyagi, said she voted in the April-May federal election last year, but could not vote in the state poll five months later.

Left makes clean sweep, campus turns red again

Agency New Delhi.

The Left Unity has emerged victorious in the Jawaharlal Nehru University Students' Union (JNUSU) election, winning all four central panel positions with clear margins over their right counterparts. Aditi Mishra, who belongs to the All India Students' Association (AISA), secured the top post of president of the union with 1,861 votes, defeating Vikas Patel of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), who received 1,488 votes.The win restores the Left's dominance on the campus after the ABVP had managed to win the joint secretary's post last year, which was a first for it in a decade.

After the results were declared, Mishra said, "It is not just a win, it is a reaffirmation of the JNU's political character."Reacting to the victory, the president of the Students' Federation of India (SFI), which is part of the Left Unity, Adarsh M Saji said, "The Left Unity panel, comprising AISA, SFI and DSF, has registered a sweeping victory, securing all four central panel posts by significant margins. K Gopika Babu, SFI's candidate for the post of vice president, won by an impressive margin, marking a major political achievement for the Left progressive movement inside the campus."

Babu garnered 3,101 votes, while Tanya Kumari of ABVP trailed behind with 1,787 votes. She is a PhD scholar at the Centre for Study of Law and Governance.

In a contest for the post of general secretary, Sunil Yadav of the Left Unity triumphed with 2,005 votes, edging past Rajeshwar Kant Dubey of the ABVP, who polled 1,901 votes. For the post of joint secretary, the Left's Danish Ali further strengthened the sweep by winning the post with 2,083 votes, defeating ABVP's Anuj Damara, who managed 1,797 votes.

The ABVP had won the post of joint secretary in 2015. For the next decade, the Left swept all four central panel seats. Last year, the ABVP had briefly broken the streak with another win of the joint secretary's post.Amid the spirited contests and shifting alliances, one of the most significant victories was of Komal Devi, who secured the School of Social Sciences (SSS) councillor seat in Thursday's JNUSU election results.

NEWS BOX

Israel strikes Hezbollah targets across southern Lebanon after evacuation orders

World . (Agency)

Israeli jets struck several towns in southern Lebanon on Thursday after urging residents to leave, marking an escalation in their near-daily strikes on the country.The airstrikes came hours after militant group Hezbollah urged the Lebanese government not to enter negotiations with Israel.

Israeli Arabic spokesperson Avichay Adraee warned residents in Tayba near the border, Teir Debba located just east of the coastal city of Tyre, and Aita al-Jabal in southern Lebanon, to flee 500 meters (about 1,600 feet) away from residential buildings they are targeting, which they say have been used by Hezbollah. It later issued more warnings for the towns of Zawtar al-Sharqiyah and Kfar Dounin.

The Israeli military said it targeted military infrastructure for Hezbollah in those areas, including "weapons storage facilities... constructed in the center of civilian-populated areas."

It accused the group of rebuilding its capabilities almost a year after a US-brokered ceasefire went into effect that ended a monthslong war. While most residents evacuated the threatened areas ahead of the strikes, Lebanon's health ministry reported one person wounded."We will not allow Hezbollah to rearm themselves, to recover, build back up its strength to threaten the state of Israel," Israeli government spokesperson Shosh Bedrosian said at a briefing Thursday.

Russia accuses Pakistani paper of serving 'foreign sponsors' in anti-Russia push

World.(Agency)

The Russian Embassy in Pakistan has launched a scathing attack on The Frontier Post, a Pakistan-based English-language daily, accusing it of publishing a "series of anti-Russian articles" and spreading "Western propaganda" against Moscow.

In a strongly worded statement posted on X, the embassy said the publication's stance had taken an overtly anti-Russian tone.The embassy questioned the newspaper's Pakistani identity that deliberately selected articles "from ardent Russophobes".

"We have taken note of a series of anti-Russian articles published in the English-language Pakistani newspaper, The Frontier Post," the embassy said. "To start with, we would like to emphasise that this periodical can hardly be called 'Pakistani,' given that its global news service is headquartered in Washington."The statement alleged that the paper's editorial board consistently chose content critical of Russian foreign policy and leadership, leaving no space for balanced reporting. "Recently, it has been impossible to find a single article in the international section of the newspaper that portrays Russia or its leadership in a positive or even neutral light," the embassy noted.

While reaffirming respect for press freedom, the embassy argued that The Frontier Post's content had crossed into propaganda. "The current barrage of anti-Russian articles containing standard Western propaganda and lacking any alternative viewpoint makes one wonder whether the editorial board's policy is based on a political agenda promoted by anti-Russian forces rather than on freedom of speech."The embassy also criticised it for its coverage choices, pointing out its failure to report on the Moscow Format of Consultations on Afghanistan held on 7 October 2025. The event, which was covered widely across Pakistani media, was reportedly "completely ignored" by the Frontier Post.

Prayed to god, please save me: Freed Israeli hostage alleges sexual violence

World .(Agency)

"I was praying to God, please save me, get me out of this already," said Rom Braslavski, a 21-year-old Israeli hostage who endured two years of captivity in Gaza, where he says he was subjected to sexual violence and daily beatings.Braslavski, who was kidnapped from the Nova music festival on October 7, 2023, is the first male hostage to publicly allege sexual abuse by Palestinian militants.

In an interview with Channel 13's Hazinor programme, excerpts of which were shared with the news agency Reuters, Braslavski recounted being stripped naked, tied up, and assaulted by one of his captors. "It was sexual violence, and its main purpose was humiliation. Its goal was to humiliate me, to crush my dignity," he said, holding back tears.

Braslavski was held by Islamic Jihad, a Palestinian militant group allied with Hamas that also took hostages during the October 7 attacks. During his captivity, the group released a video showing him appearing skeletal and distressed.An Islamic Jihad official denied the allegation, calling it "incorrect" without providing further explanation.An Israeli government spokesperson described Braslavski's testimony as "living proof" of what she called the true nature of Gaza's militant organisations.

At least four women hostages have previously come forward with accounts of sexual abuse during captivity. In March 2024, United Nations experts reported finding "clear and convincing information" that some hostages taken to Gaza were subjected to sexual violence. Hamas, which held most of the hostages, has denied the allegations.Braslavski also detailed enduring regular beatings. "You just pray to God for it to stop. And while you're there, every day, with every beating, every day, you say to yourself, I have completed another day in hell," he said.

Trump to blame for Mamdani victory: Why MAGA knives are out for their hero

The MAGA crowd, Donald Trump's support base, has gone berserk after electoral defeats in mayoral and gubernatorial polls. Zohran Mamdani's victory in New York City is particularly stinging. Supporters are blaming Trump, saying his obsession with foreign politics and ignoring crucial domestic issues caused the setbacks.

World . (Agency)

US President Donald Trump, the hero of the MAGA movement, is now facing backlash from his own supporters following a bunch of Republican defeats in the US, most notably in New York City, where Zohran Mamdani became the first Muslim-immigrant to win the mayoralty. Now, the MAGA base is openly blaming Trump, arguing that his focus on foreign policy distracted him from focussing on domestic issues, leaving the Grand Old Party (GOP) vulnerable.Tuesday's elections dealt heavy losses to Republicans in Virginia, New Jersey, California, and New York City, with Mamdani's high-profile victory drawing national and international attention.

The defeats have sparked a blame game among Trump loyalists, raising questions about whether the president's influence can still deliver results for the GOP.Mike Cernovich, Jack Posobiec, Laura Loomer, and Michael Boyle are among MAGA leaders who questioned Trump over the loss.

Additionally, Indian-origin Republican leader Vivek Ramaswamy and Trump's 2024 campaign political director James Blair suggested that domestic issues contributed to the GOP's electoral defeats.

Many MAGA supporters slammed Trump for focusing more on foreign issues than problems at home, while others attributed the defeat to Republicans' internal feuds amid a string of texting scandals.Meanwhile, voters say Trump and Republicans in Congress are more to blame for the ongoing government shutdown, according to a new NBC News poll.

The shutdown, now in its second month and the longest in US history, has caused flight delays across the country, disrupted services, and left around 1.4 million federal employees on unpaid leave or working without pay, the BBC reported.

MAGA leaders have criticised Trump for ignoring domestic issues and focusing on foreign affairs.Majorities of voters disapprove of Trump's job performance. In many states, including Virginia, more than half of the electorate saw their vote as sending a message to Trump, according to CNN.

Voters appeared particularly critical of Trump's tariff and immigration policies.Right-wing personality Mike Cernovich slammed Trump for prioritising foreign policy over domestic issues."Trump spent all year on the Middle East, his big donors loved it, the voters did not. Virginia is going to be under a Democrat supermajority now," Cernovich wrote on X Tuesday evening."Keep listening to Mark Levin (Fox News host), Mr President, and you'll be back to impeachment trials in 2026," he added in another post on X.

Why Kazakhstan joined the Abraham Accords: A new geopolitical balancing act

World . (Agency)

Kazakhstan has officially joined the Abraham Accords — the United States-brokered diplomatic framework that normalised relations between Israel and several Muslim-majority nations. While Kazakhstan has already maintained full diplomatic and economic ties with Israel, its entry into the accords carries significant symbolic and strategic weight, particularly in the context of shifting geopolitics in Central Asia and West Asia.

The move coincides with President Kassym-Jomart Tokayev's visit to Washington for meetings with President Donald Trump, alongside the leaders of other Central Asian states. The summit forms part of Washington's renewed attempt to strengthen its influence in a region long regarded as part of Russia's geopolitical orbit and now increasingly drawn into China's economic sphere. Central Asia today is at the centre of a quiet strategic competition, and the United States is attempting to reinsert itself into regional affairs.

For Washington, Kazakhstan joining the accords signals that the United States remains a relevant player in shaping political alignments across the Muslim world, even as the Gaza crisis places diplomatic pressure on Israel's partnerships. The expansion of the accords had largely stalled during the conflict, but Kazakhstan's accession allows Washington to demonstrate continued diplomatic momentum.For Kazakhstan, the decision aligns with its long-standing "multi-vector" foreign policy, a delicate balancing act that seeks to maintain positive relations with Russia, China, Western states, and regional partners simultaneously. By formalising its role within the Abraham Accords, Kazakhstan positions itself as a diplomatic bridge: between Israel and Muslim states, between the East and the West, and between Washington and the broader region.There is also a clear economic dimension. Kazakhstan is attempting to diversify its economy beyond oil and extractive industries.

Body of Indian MBBS student, missing for 19 days in Russia, found in dam

World . (Agency)

A 22-year-old medical student from Rajasthan's Alwar, who had been missing in Russia for nearly three weeks, was found dead near a dam in Ufa city, his family members confirmed on Thursday.The student, identified as Ajit Singh Chaudhary, was pursuing an MBBS degree at Russia's Bashkir State Medical University since 2023.Ajit had gone missing on October 19 after stepping out of his hostel around 11 am, telling friends he would return within half an hour after buying milk. He never came back.

Days after his disappearance, local authorities found his clothes, phone, and shoes near the White River. Nineteen days later, Ajit's body was recovered from a dam adjoining the same river.The Indian Embassy in Moscow informed both the family and local representatives in Alwar about the discovery.

Fellow students identified the body, and officials said arrangements are being made to conduct a post-mortem through a medical board before sending the remains back to India. The repatriation process, coordinated between the Indian Embassy and Russian authorities, is expected to take two to three days, officials said.

Ajit's suspicious death has left his family and village in shock. Relatives said they had sold nearly three bighas of land to fund his medical education in Russia. "We sent him with so many dreams. Now, we are only waiting for his body to return," a family member said.

Local leaders confirmed receiving updates from the Indian mission. Community members held a meeting at the Alwar Jat hostel, expressing anger over what they called a slow response to the student's disappearance and urging the government to ensure his body is brought back swiftly.

Congress leader Jitendra Singh Alwar expressed deep grief over the death, calling the circumstances 'suspicious'. In a post on X, he urged the External Affairs Minister, S Jaishankar, to expedite the repatriation and ensure a thorough investigation."An untoward incident has occurred with the boy in suspicious circumstances; it must be investigated with complete seriousness. The family should not have to run around your offices any more," Jitendra Singh Alwar, a former Union Minister, wrote.

Ajit's parents, Roop Singh and Santra Devi, are devastated and his family members have demanded a detailed inquiry into how the young student ended up dead in a foreign land.

US Supreme Court allows Trump to enforce two-gender passport policy

world.(Agency)

The US Supreme Court on Thursday allowed President Donald Trump's administration to enforce a policy restricting passport gender markers to only "male" or "female," reversing lower-court orders and igniting sharp debate over transgender rights and safety.

The ruling permits the administration to proceed with the policy while a lawsuit challenging it continues. It halts a lower-court order that had required the State Department to let applicants choose "M," "F," or "X" on passports to align with their gender identity. The court's three liberal justices dissented, according to The Associated Press.

The decision marks another victory for Trump on the court's emergency docket. Since the beginning of his second term, the Supreme Court has issued nearly two dozen short-term orders favouring his administration in various policy disputes, including one that barred transgender people from serving in the military.

In an unsigned order, the conservative majority said the policy does not violate equal protection principles. "Displaying passport holders' sex at birth no more offends equal protection principles than displaying their country of birth," the court wrote. "In both cases, the Government is merely attesting to a historical fact without subjecting anyone to differential treatment."

Justice Ketanji Brown Jackson, joined by the court's two other liberal justices, issued a strong dissent. She warned that the ruling puts transgender and nonbinary Americans at risk. "This Court has once again paved the way for the immediate infliction of injury without adequate (or, really, any) justification," Jackson wrote, arguing that the policy.

Nuclear hotspots: Where the world tests its most dangerous weapons

World . (Agency)

.Last week, just before his meeting with China's Xi Jinping, US President Donald Trump stirred a hornet's nest by saying the US would resume nuclear weapons testing. Five days later, Russian President Vladimir Putin asked his security council to prepare for nuclear tests. The developments have raised concerns of a destabilising nuclear arms race.Trump has justified his move by claiming that Russia, China and Pakistan were testing nuclear weapons. US energy secretary Chris Wright, however, clarified that the President didn't mean full-scale nuclear tests. But Trump's statement travelled around the world, particularly in Beijing, Moscow and Pyongyang.If the US does indeed test weapons, it will trigger a global chain reaction. Russia and China could follow the US and begin their own tests.At the Kremlin meeting on November 5, Russian Defence Minister Andrei Belousov advised immediate preparations for full-scale nuclear testing. The readiness of the forces and assets at the Central Test Site on the Novaya Zemlya archipelago, he said, made it possible for tests to be carried out within a short timeframe.Israel is the only one of the nine nuclear-weapon states to have never conducted a confirmed nuclear test. The eight others have detonated over 2,000 nuclear devices since 1945. Over 80% of these tests were carried out by the US and the former USSR.

HOW ARE NUCLEAR WEAPON TEST SITES CHOSEN?

From Nevada to North Korea, choosing a nuclear test site is a meticulous, multi-step process balancing science, secrecy and safety. There are three key factors that go into making up a nuclear weapons test site.

Geological stability

Open nuclear testing was banned in 1963. Countries thus have to rely on deep-buried shafts to test their weapons. Hence, geology becomes an important factor. The area must be seismically quiet - meaning it shouldn't have active faults that could trigger earthquakes. It must have hard, dry rock that won't leak radioactive gases when the shaft is sealed.

Hydrogeology

The test site must be deep, hundreds of metres below the ground, so that the radiation does not poison the water table. At India's test site at Pokharan, for instance, the water table is more than 500 metres deep.

Buffer zones

It must be ensured that there is no human habitation, and operational secrecy should be preserved to prevent other countries from detecting nuclear tests.

WORLD'S NUCLEAR WEAPON TEST SITES

United States

The US was the first country to test and use nuclear weapons.

NEWS BOX

Hong Kong Sixes: Livestreaming details, full squads as India play Pakistan

New Delhi. (Agency)

Dinesh Karthik's India will face Abbas Afridi's Pakistan in the Hong Kong Sixes on Friday, November 7, as the arch-rivals renew their cricketing rivalry in a unique six-a-side format. The high-voltage clash comes amid the ongoing standoff between the two nations, adding another layer of intrigue to an already fiery contest.

India and Pakistan met three times earlier this year in September during the Asia Cup, and each encounter had its share of drama, both on and off the field. Despite being an invitational tournament, the latest meeting promises to be no different, with both teams eager to assert their dominance at the Tin Kwong Road Recreation Ground in Hong Kong.

The Hong Kong Sixes is known for its fast-paced, entertaining brand of cricket, where each side fields six players. The format often produces explosive batting displays and quick results, making it a fan favourite among followers of the shorter formats. This year's edition has attracted plenty of attention, especially with several familiar Indian names returning to the field.

Dinesh Karthik will lead a strong Indian squad that features experienced campaigners such as Stuart Binny, Bharat Chipli, Abhimanyu Mithun, Shahbaz Nadeem, Priyank Panchal, and Robin Uthappa. Pakistan, under the captaincy of Abbas Afridi, have chosen a younger side with players like Abdul Samad, Khawaja Mohammad Nafay, Maaz Sadaqat, Mohammad Shahzad, Saad Masood, and Shahid Aziz. Although Pakistan's squad lacks major international stars, their youthful energy and aggressive style could pose a strong challenge.

The match between India and Pakistan will begin at 1:05 PM IST on Friday, November 7, at the Tin Kwong Road Recreation Ground in Hong Kong. Fans in India can watch the live telecast on Sony Sports Ten 5, while live streaming will be available on the FanCode app and website.

Bangladesh Cricket Board to investigate Jahanara Alam's sexual harassment allegations

New Delhi. (Agency)

The Bangladesh Cricket Board (BCB) has initiated an investigation into sexual harassment allegations raised by former Bangladesh women's cricket captain Jahanara Alam, who claims a former selector and other board officials acted inappropriately toward her during the 2022 ODI World Cup.The BCB announced the formation of a committee to conduct an inquiry and submit its findings and recommendations within 15 working days. The board stated that it will take appropriate actions based on the committee's report.

In a statement released just before midnight, the BCB said: "The Bangladesh Cricket Board (BCB) has noted with concern the allegations reported in the media made by a former member of the Bangladesh national women's cricket team regarding alleged misconduct by certain individuals associated with the team. As the matter is of a sensitive nature, the BCB has decided to form a committee to investigate the allegations thoroughly.

The committee will submit its findings and recommendations within 15 working days. The BCB is committed to ensuring a safe, respectful, and professional environment for all its players and personnel. The Board takes such matters with utmost seriousness and will take appropriate action based on the findings of the investigation."

JAHANARA's HARRASSMENT CLAIMS

Jahanara, who now resides in Australia, stated in an interview with journalist Riasad Azim that a former selector behaved inappropriately toward her when he was the women's team selector and manager. She claimed that he asked her lewd questions and that a couple of BCB officials also acted inappropriately with her. She said she reported the incident to former BCB director Shafiul Islam Nadel and the board's chief executive, Nizamuddin Chowdhury.

"I faced several times (indecent proposal) not once. Definitely, when we are involved with the team, we cannot speak out about many things, even if we want to. When it comes to your bread and butter, when you are known by a few people, you cannot say or protest many things even if you want to," Jahanara told The Riasat Azim YouTube channel.

After T20I retirement, Kane Williamson pulls out of ODI series against West Indies

Kane Williamson will not feature in New Zealand's ODI squad for the upcoming three-match series against the West Indies, following his recent retirement from T20 internationals.

New Delhi. (Agency)

Kane Williamson will sit out New Zealand's upcoming three-match ODI series against the West Indies, marking the start of a new chapter for the Black Caps following his recent T20I retirement. The veteran batter, who remains pivotal to New Zealand's Test ambitions, has opted to focus on preparations for the ICC World Test Championship series against the Caribbean side, set to begin next month.

The ODI series, which begins in Christchurch on November 16, will see Mitchell Santner leading the side in Williamson's absence. The selectors have opted for a well-balanced squad that blends experience with emerging talent, rewarding players who impressed during New Zealand's recent 2-1 ODI series victory over England.Pace bowler Matt Henry makes a welcome return to the side, strengthening the bowling attack after a spell out of action. However, key players such as Finn Allen and Lockie Ferguson remain unavailable due to injuries.

Head coach Rob Walter expressed confidence in the group selected to face the West Indies, praising the recent performances of Blair Tickner. "We couldn't have asked for more from Ticks against England," Walter said. "He brought plenty of energy, and his pace and bounce proved to be a real test for some of the best batters in the world."

Walter added that the selection reflects New Zealand's commitment to rewarding consistent performers. "It was pleasing to see him come in at short notice and perform at that level. That's a testament to the hard work he's been putting in away from the group," he said. "It's great to be able to keep rewarding players who work hard and deliver when given the opportunity, and we know he'll be a big asset for us in another important series."

The 14-member squad for the series includes Mitchell Santner (captain), Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Zak Foulkes, Matt Henry, Kyle Jamieson, Tom Latham, Daryl Mitchell, Rachin Ravindra, Nathan Smith, Blair Tickner, and Will Young.

Looking ahead, Walter acknowledged the challenge posed by the West Indies, describing them as a side full of match-winners. "The West Indies are always dangerous and have a host of players who can change a game in any format," he said. "We're expecting a competitive contest throughout the series."

The three ODIs will be played in Christchurch (November 16), Napier (November 19), and Hamilton (November 22). Walter stressed the importance of the series in helping the side build towards future tournaments. "It's another key series for us as we continue to grow and improve in the format, so we're looking forward to what's to come," he concluded.

Turkey orders arrest of 17 referees, one club president in football betting probe

New Delhi. (Agency)

Turkish prosecutors have ordered the arrest of 21 individuals, including 17 referees and a Super Lig club president, as part of an extensive investigation into alleged football betting and match-fixing, state media reported on Friday.According to the Istanbul Chief Prosecutor's Office, 18 of the 21 suspects have already been detained in operations conducted across 12 cities. The suspects face charges ranging from abuse of duty and manipulating match results to spreading misleading information on social media. Among those detained are a club president from Turkey's top division, a former club owner, and a former association president.

The arrests mark an explosive escalation in a scandal that has rocked Turkish football in recent weeks. It comes just days after the Turkish Football Federation (TFF) suspended 149 referees and assistant referees for betting on football matches, a serious breach of national and international football regulations.

In its own investigation, the TFF's disciplinary board imposed bans ranging from eight to 12 months on 149 officials involved in betting, with three more cases still under review. The full list of penalised officials has been published on the federation's official website.

The scale of the betting activity uncovered by the TFF has stunned football authorities and fans alike. The federation's five-year probe revealed that 371 of Turkey's 571 active referees had betting accounts, and 152 of them were actively gambling. While some referees were found to have placed only a handful of bets, 42 had wagered on more than 1,000 matches each. In one extreme case, a referee had placed a staggering 18,227 bets.The findings have triggered what TFF president Ibrahim Haciosmanoglu called a "moral crisis" in Turkish football."There is a moral crisis in Turkish football. There is no such thing as structure. The fundamental problem at the core of Turkish football is an ethical one," Haciosmanoglu told CNN Trk on Friday.

Suryakumar Yadav out of form? Ashwin defends captain's 10-ball 20 knock vs Australia

New Delhi. (Agency)

Ravichandran Ashwin has come out in support of India captain Suryakumar Yadav amid his lean patch in T20Is. Speaking on his YouTube channel after the fourth T20I between India and Australia, Ashwin said that although Suryakumar's short innings might not look impressive on paper, his quick bursts often have an impact that goes beyond numbers.

Suryakumar Yadav has endured a noticeable dip in form since taking over the T20I captaincy. Once regarded as one of the most explosive batters in the shortest format, he has managed to score only two half-centuries since the T20 World Cup 2024. Despite recent struggles, he showed signs of rhythm in the fourth T20I against Australia on Thursday, November 6.

Coming in at a crucial stage, Suryakumar struck two sixes off Adam Zampa immediately after arriving at the crease but was dismissed in the 16th over while attempting another big shot against Xavier Bartlett. Reflecting on the 10-ball cameo, Ashwin praised the intent and the value of those quick runs in a game situation that required momentum in the middle overs.

"Ten balls for 20 from Suryakumar Yadav was extremely valuable. I always think in T20 cricket, 10 balls for 20 at a 200 strike rate is more valuable. Even today, Abhishek and Shubman had a decent partnership at the top, so Surya came in and gave that amazing impetus and momentum. I would always think 10 balls for 20 is far more valuable than a strike rate of less than 125, 120, or 130 in a T20 game, unless, of course, you are chasing a total," Ashwin said on his channel.

"If you are chasing and players are going all out, one side has to play in double gear. But today, everyone knew that 160 was a good score. The way Shubman paced the innings was the way he had to play, and he did that. So credit where it's due, but I am happy with Surya's 10-ball-20. What he could do, he did," Ashwin added.

India head coach Gautam Gambhir has adopted a high-octane approach with the bat and has repeatedly said that he is fine with players getting out while trying to play attacking shots, as long as one of them carries on to make a big score.

On Thursday, Shubman Gill anchored the Indian innings with a 46-run knock on a tricky surface at the Carrara Oval. India set a target of 167 runs for Australia and bowled out the hosts for just 119 in reply.The teams will now travel to Brisbane for the fifth and final T20I of the series. India currently lead 2–1 and will look to land the final knockout punch at the 'Fortress Gabba'.

Manchester United's Ruben Amorim responds to Cristiano Ronaldo's criticism

New Delhi. (Agency)

Manchester United head coach Ruben Amorim has admitted that the club "made a lot of mistakes" in the past but urged everyone to focus on the future, after Cristiano Ronaldo suggested that he could not "work miracles" with the current squad.

In a wide-ranging interview with Piers Morgan earlier this week, Ronaldo, who won eight major trophies during his two spells at Old Trafford, said that while he believed Amorim was doing a good job, the Portuguese coach would struggle without proper structural support from the club.

"We say in Portugal, 'miracles only happen in Fatima,'" the 40-year-old Al-Nassr forward said. "United are not on a good path. Amorim is not going to do miracles because they don't have a structure. You have to work with smart people to create a base for the future."

The former Manchester United and Real Madrid forward, who shared the national dressing room with Amorim for Portugal, added that the problems at Old Trafford run deeper than coaching."While some of the players are good, others do not have the mind of a player for this club," Ronaldo said. "You have to work with smart people to create a base for the future. Right now, they don't have a structure."Ronaldo also expressed sadness over what he called United's "decline," warning that the club lacked long-term vision and that Amorim could not be expected to fix everything overnight.

Speaking to the media ahead of United's Premier League trip to Tottenham Hotspur on Saturday (12:30 GMT), Amorim chose not to respond directly to Ronaldo's remarks but made his message clear: the past cannot be changed, and the club's energy must now be directed toward progress.

"He [Ronaldo] knows he has a huge impact with everything he says," Amorim said on Thursday. "We know as a club we made a lot of mistakes in the past. We are trying to change that. Let's not focus on what happened [in the past].

"We are changing a lot of things; the structure, the way we do things, the way we want the players to behave. We are improving. Let's forget a little bit the past."

Amorim, who replaced Erik ten Hag in November 2024, has overseen a period of gradual stabilisation. United have shown signs of progress under his leadership, climbing to eighth place in the Premier League - just two points off second - after a four-game unbeaten run.

Mandhana vs Wolvaardt: Mercurial batters nominated for player of the month award

Women's World Cup: India's Smriti Mandhana has been nominated for the ICC Women's Player of the Month for October following her outstanding performances in the tournament. She will be vying for the award against Laura Wolvaardt and Ashleigh Gardner.

New Delhi. (Agency)

After leading India's Women's World Cup charge with the bat, vice-captain Smriti Mandhana has been nominated for the ICC Women's Player of the Month for October. Opening the innings for India, Mandhana produced a series of brilliant performances, scoring 434 runs at an average of 54.25, guiding India to their maiden Women's ODI World Cup Trophy.Mandhana will compete for the honour alongside South African captain Laura Wolvaardt, who enjoyed a tournament of her life, and Australia's dynamic batting all-rounder Ashleigh Gardner, who impressed with both bat and ball throughout October.

Mandhana's leadership at the top of the order, particularly her partnerships with fellow opener Pratika Rawal, created a buzz in the tournament. After a relatively quiet start, she came into her own with a blistering 80 against seven-time champions Australia, followed by a combative 88 against England.

Though India lost both matches, Mandhana's form was undeniable. In the must-win clash against New Zealand, she rose to the occasion with a brilliant 109, forging a match-winning 212-run partnership with Rawal. In the final against South Africa, she provided a solid start with 45 runs and shared a century partnership with Shafali Verma at the top.

Wolvaardt, meanwhile, turned around South Africa's campaign after a humiliating 69-run opening defeat to England, scoring 571 runs at an astounding average of 71.37. She played a pivotal 70 against India in the league stage, half-centuries against Sri Lanka and Pakistan, and a record 169 in the semifinal against England, guiding the Proteas to the final. She then scored 101 in the final, though India's collective effort denied South Africa a maiden World Cup title.

Australia's Gardner contributed heavily in almost every game, scoring centuries against New Zealand (115) and England (104 not out), while also taking seven wickets in October, proving her value as a genuine all-rounder.

Deepti Sharma Snubbed

Surprisingly, player of the tournament in the Women's ODI World Cup, Deepti Sharma was snubbed from the list of nominees. Deepti became the first player, man or woman, to achieve a double of 200 runs and 20 wickets in a single edition of the tournament.

Nikki Tamboli's

Boyfriend Arbaaz Patel 'Nearly Confirmed' To Enter Bigg Boss 19? Find Out

After impressing everyone with his stint in Rise and Fall, Nikki Tamboli's boyfriend, Arbaaz Patel, is now likely to enter Bigg Boss 19. If a viral post on X is to be believed, Arbaaz has been approached by the makers to participate in Salman Khan's show and is 'nearly confirmed' as a wildcard contestant."As Per Strong rumours, The Nearly Confirmed Name That Is coming is of #ArbazPatel ," the viral post read. Check it out here:

Previously, Malti Chahar also entered the Bigg Boss 19 house as a wild card contestant. The show, which premiered in August this year, is also likely to get an extension of three week. As per Bigg Boss Khabari reports, the reality show is likely to get an extension of three to four weeks. While there has been no official announcement so far, reports suggest that the move is being discussed due to the growing popularity of the season.

Earlier reports claimed Bigg Boss 19 would conclude on December 7. However, if the makers extend the show, the finale will be postponed by almost a month.

Arbaaz Patel Was Recently Seen On Rise And Fall

Arbaaz Patel was recently seen in Rise and Fall. Initially placed in the "Rise" group, he earned praise for his leadership and ability to form alliances. However, mid-season, a series of confrontations and trust issues led to his downfall, pushing him into the "Fall" zone. Despite facing constant challenges and emotional lows, Arbaaz managed to win audiences over with his honesty and resilience. In one of the episodes, Nikki Tamboli also appeared as a guest to cheer her beau.Rise and Fall was won by Arjun Bijlani.

Tejasswi Prakash's

Infectious Smile Adds Glam To Laughter Chefs 3 Red Carpet

Laughter Chefs: Unlimited Entertainment, the Bharti Singh-hosted cooking-based reality show, is all set to make a return with its third season soon. This time, the viewers will see several new celebrities who will engage in the chaotic blend of cooking challenges and comedy. Among all, Bigg Boss 15 winner and TV actress Tejasswi Prakash is also a part of the lead cast of the show.Reportedly, in the forthcoming season, the actress will be paired with her boyfriend and actor Karan Kundrra.

Tejasswi Prakash Spotted On Sets

On Thursday, the Swarigini actress was papped on the sets of Laughter Chefs 3. In a video shared on Instagram, the diva is seen striking a pose in front of the shutterbugs stationed at the location and flaunting her adorable smile.

Coming to her look, the actress opted for a neon-green outfit featuring a sleeveless top paired with a matching long skirt. She accessorised her look with silver heels, kept her hair open in soft curls and let them cascade down her shoulders.

What Did Fans Say?

In no time, the comment section was flooded with reactions from fans and admirers. An Instagram user wrote, "Gorgeous Teju." Another one commented, "Beautiful." One of them shared, "Stunning."

Laughter Chefs 3 Plot

Apart from Tejasswi, other new faces that will be seen in Laughter Chefs 3 include: Vivian Dsena, Debina Bonnerjee, Gurmeet Chaudhary, Isha Malviya and Eisha Singh. Jannat Zubair will be making a return to the show after Season 1.

Krushna Abhishek, Kashmera Shah, Karan Kundrra, Elvish Yadav, Aly Goni, Abhishek Kumar and Samarth Jurel will also be returning to entertain the audience with their comic timing and culinary art.With such an interesting lineup and star power, Laughter Chefs season 3 already looks like a perfect recipe for entertainment and laughter.

Tejasswi Prakash's Work Front

She has been a part of numerous shows, including Swaragini: Jodein Rishton Ke Sur, Pehredaar Piya Ki, Sanskaar: Dharohar Apno Ki and Naagin 6, among others.

Mira Rajput's Fitness Advice For Fans This Winter: 'Get Moving'

Mira Rajput Kapoor, wife of Bollywood heartthrob Shahid Kapoor, is a fitness fanatic, and her toned physique and radiant skin are proof of that. Known for her regular gym appearances and wellness tips on social media, the 31-year-old continues to motivate fans with her regular exercise routine that includes some rigorous workouts to stay fit. Mother of two, Mira, regularly shares glimpses from her workout sessions, yoga practices, and lifestyle habits, encouraging followers to prioritise their health.

Her latest offering is another inspirational post for those who are too lazy to start their workout routine. Taking to Instagram, she shared a glimpse of her early morning workout routine.

Mira posted a distant mirror selfie from her gym along with the caption, "Get moving and good morning."

Mira Rajput's On Balancing Wellness With Motherhood

In an interview with Hello! Magazine, Mira earlier talked about how she manages to stay active while juggling motherhood. As a mom to Misha and Zain, she revealed that she has gradually reshaped her fitness routine to align with her energy levels and her family's needs.

Proving that health and parenting can go hand in hand, she stated, "I like to work out three or four times a week. I like Pilates and functional training with light weights. Earlier, I used to feel an energy dip around 3pm. And that's when my kids get home from school. So I decided to scale back the intensity of my workouts to be able to spend time with my family without feeling exhausted or cranky… The most important factor, though, is sleep. It's so underrated!"

What Is Mira Rajput Up To These Days?

Beyond fitness, Mira Rajput has successfully transitioned from homemaker to entrepreneur. She recently stepped into the world of wellness with her wellness centre, Dhun, located in Mumbai's Bandra. The venture comes after she co-founded Akind, a skincare brand focused on mindful, clean beauty.

Shraddha Kapoor Trains In Lavani For Vithabai Narayangaonkar Biopic Eetha: Report

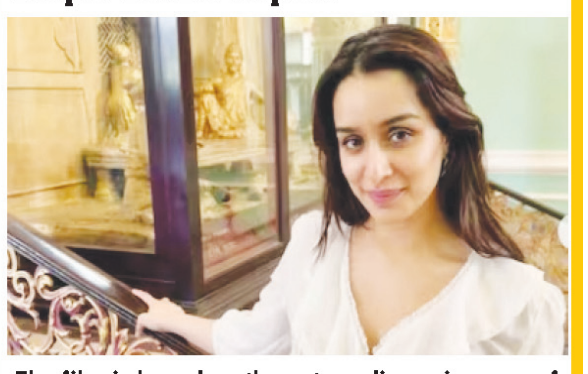

The film is based on the extraordinary journey of Vithabai Narayangaonkar, one of Maharashtra's most revered Tamasha performers.

Shraddha Kapoor has reportedly begun shooting for her next film, which is a biopic on legendary Marathi folk performer Vithabai Narayangaonkar and has been titled Eetha. The actress will be playing the tutorial role. Fresh updates mention that she has reportedly begun training in Lavni, the traditional Maharashtrian dance form.Midday has quoted a source saying, "With her mother Shivangi Kolhapure being Maharashtrian, Shraddha is deeply steeped in the culture. Another advantage was her dancing skill since it formed a big part of Vithabai's life story. Shraddha picked up Lavani and Gavlan, the two folk dance forms that originated in Maharashtra. They are widely used in Tamasha, which traditionally combines storytelling with singing, dancing, and satire."

About Marathi Folk Legend Vithabai In Laxman Utekar's Biopic Eetha

Production for the film officially commenced on November 1, 2025. The title Eetha is derived from a regional pronunciation of Vitha, the affectionate name by which the legendary performer was known in parts of Maharashtra. The film is based on the extraordinary journey of Vithabai Narayangaonkar, one of Maharashtra's most revered Tamasha performers. Born in July 1935 in Pandharpur, located in Solapur district, Vithabai came from a family deeply rooted in traditional folk performance. She began her career as a child and went on to become an iconic figure in the world of Lavani and Tamasha theatre. Known for her commanding stage presence, expressive voice, and high-energy performances, Vithabai's contribution to Indian folk culture earned her two President's Awards, first in 1957 and later in 1990.

The title Eetha carries local significance, representing how Vitha, a familiar form of the artist's name, is pronounced in certain parts of rural Maharashtra. Utekar, who is known for blending emotional depth with realism in his storytelling, is expected to highlight not just the artist's career but also the personal struggles behind her celebrated public life.

Shraddha Kapoor's upcoming work

The actor is set to return in Stree 3, scheduled for release in August 2027. She also has the ambitious fantasy trilogy Naagin lined up, in which she will play the titular role. Dinesh Vijan had explained the idea behind the MHCU and even revealed why Stree 3 won't get a 2026 release.